

पेज 05
देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी

साप्ताहिक
# शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 16 नवंबर से 22 नवंबर 2026
हम दिखाएंगे आईना...



पेज 08
कम पैदावार में भी अन्नदाताओं को पूरा लाभ

वर्ष : 02 अंक : 37 पृष्ठ : 08 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 04 खुरचनः लिफाफे का अवसान, तोहफों का नया संविधान..!

## धरमजयगढ़ का ही चयन क्यों ?

(सुकांत राजपूत/रायपुर)

सियासी मुल्ला सवाल उठाने लगे है। जनजातीय गौरव कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री हो या फिर पूरी भाजपा; रायगढ़ जिले की एक विधानसभा सीट धरमजयगढ़ को ही क्यों चुनी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन स्मृति ईरानी और प्रदेश संगठन भी धरमजयगढ़ के चक्कर काटते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी वह रायगढ़ जिले की एक विधानसभा सीट धरमजयगढ़। नितिन नवीन से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी पहुँच गई थीं। आखिर धरमजयगढ़ इतना खास क्यों हो जाता है। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित इस क्षेत्र में नितिन नवीन के पहुंचने के मायने क्या है और क्यों यहां कांग्रेस लगातार जीत रही है।

सबसे पहले बात धरमजयगढ़ की करते हैं। यह क्षेत्र घने वनों से घिरा हुआ है। यहां खनिज संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है। साथ ही हाथियों का गलियारा भी इस क्षेत्र से होकर जाता है। यही नहीं धरमजयगढ़ के आसपास की करीब 10 विधानसभा सीट लेलूंगा, पत्थलगांव, जशपुर, कुनकुरी, सीतापुर आदिवासी बहुल है और यहां आदिवासी वर्ग से ही विधायक चुने जाते हैं। भाजपा ने पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी इसी क्षेत्र से आते हैं। मोदी सरकार में साय जब केंद्रीय राज्यमंत्री थे, तो इसी रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट है। यहां सिर्फ दो बार बीजेपी की जीत हुई है।

2018 के के विधानसभा चुनाव में सरगुजा और रायगढ़ की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 2023 के चुनाव में परिणाम उलट आया और भाजपा को बड़ी जीत मिली। हालांकि इससे लगे क्षेत्र जांजगीर चांपा में अभी कांग्रेस के विधायक बहुमत में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एससी वोटरों को साधने के लिए अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत जांजगीर से की थी। वहां सभी बड़े नेताओं का दौरा हुआ था। अब बीजेपी की नजर आदिवासी वोटरों पर है। बस्तर में नक्सलवाद के खातमें के बाद भाजपाई मान रही है कि उनके पक्ष में माहौल हैं। जबकि सरगुजा में नए सिरे से स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत को महसूस किया जा रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में भी भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि वोटर पार्टी के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ आ सकते हैं।

दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा खनिज संसाधन का है। रायगढ़ से लेकर सरगुजा तक कोयला खदानों को लेकर आदिवासी वर्ग का असंतोष देखने को मिल रहा है। कई जगह पर उग्र आंदोलन भी देखने को मिला है। आदिवासियों की नाराजगी के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए बीजेपी वहां संगठन को मजबूत करना चाह रही है। जिससे आदिवासी वर्ग की बातें संगठन और सरकार तक पहुंच सके।

जल जंगल जमीन की बात करने वाले आदिवासी समुदाय भले ही अभी भाजपा के साथ है, लेकिन उनकी मुख्य मांगे विकास है। पर्यावरण को बचाकर विकास और जल जंगल जमीन को बचाकर विकास है। राज्य बनने के बाद लगभग हर सरकार ने हाथियों के कॉरिडोर की बात की। हाथियों को बचाने की बात की और हाथियों से होने वाली जनहानि को रोकने की बात की। लेकिन चुनावी राजनीति में हाथी सिर्फ चर्चा का विषय है। कुल मिलाकर जब भाजपा सरकार धर्मजयगढ़ पहुंचें तो वहां उनकी बात सिर्फ जनजातीय राजनीति और चुनावी ना हो। धर्मजयगढ़ से लेकर आसपास के 50-100 किलोमीटर की खराब सड़कों पर भी बात हो। खदानों से निकलने वाले प्रदूषण पर बात हो और आम आदिवासी के जीवन में किस तरह उजाला आएगा, उस पर भी बात हो। अब बात सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित 11 विधानसभा सीट की कर लेते हैं। रायगढ़ की दो विधानसभा सीट धरमजयगढ़ और लैलूंगा कांग्रेस के कब्जे में है। जशपुर जिले की तीन सीट जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव में बीजेपी के विधायक हैं। वही सरगुजा की भरतपुर सोनहत, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा और सीतापुर विधानसभा सीट भी बीजेपी के पास ही है

रायगढ़ के धरमजयगढ़ में पिछले तीन चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार लालजीत राठिया की जीत हो रही है। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में 2013 में भाजपा की सुनीति राठिया ने जीत दर्ज की थी, लेकिन पिछले दो चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो रही है। 2018 के चुनाव में चक्रधर सिधार और 2023 के चुनाव में विद्यावती सिधार कांग्रेस विधायक के रूप में चुनी गई। रायगढ़ जिले में भाजपा सिर्फ एक विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है, जिस पर मंत्री ओपी चौधरी विधायक है।

जशपुर जिले की जशपुर और कुनकुरी में हर बार मतदाता विधायक चुनने में पार्टी बदल देते हैं। वहीं पत्थलगांव में लगातार कांग्रेस की जीत हो रही थी, लेकिन इस चुनाव में मतदाताओं ने बीजेपी को समर्थन दिया है। जशपुर से रायमुनि भगत, कुनकुरी से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पत्थलगांव से गोमती सायं विधायक हैं। सरगुजा के प्रतापपुर और भरतपुर सोनहत में कांग्रेस और भाजपा विधायकों की अदला बदली होती रहती है। रामानुजगंज, सामरी और लुण्ड्रा में दो चुनाव बाद भाजपा की वापसी हुई है। जबकि सीतापुर में बीजेपी को पहली बार जीत मिली है।

### 36 सीटों पर है भाजपा की नजर

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनका फर्स्ट विजिट कांग्रेस के उस गढ़ में हो रहा, जहां 46 साल में बीजेपी सिर्फ दो बार जीत पाई है। 1980 में धर्मजयगढ़ विधानसभा सीट के बनने के बाद चनेशराम राठिया लगातार पांच बार विधायक बने और एमपी के समय वे पीडब्लूडी जैसे अहम विभाग के मिनिस्टर रहे। 2003 और 2008 में बीजेपी के ओमप्रकाश राठिया ने जरूर जीत दर्ज की। मगर उनके बाद 2013, 2018 और 2023 के चुनाव में कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया जीत की हैट्रिक बना चुके हैं।

दरअसल, बीजेपी कांग्रेस के उस परंपरागत गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है, जहां बरसों से उसे जीत नहीं मिली है। इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए धर्मजयगढ़ को चुना गया। वैसे, प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी ने भी छत्तीसगढ़ दौरे में कांग्रेस के उन अभेद्य गढ़ों के बारे में बात की थी। चर्चा में, ये बात आई थी कि कांग्रेस ने आखिर विपरीत हवा होने के बाद भी 36 सीटें कैसे जीत ली। बता दें, छत्तीसगढ़ में कई ऐसी सीटें हैं, जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। मसलन, बिलासपुर जिले की कोटा विधानसभा सीट। बीजेपी संगठन की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि राज्य बनने के बाद करीब 18 साल की सत्ता में वहां के लिए ढंग का एक प्रत्याशी तैयार नहीं कर पाई। पिछले विधानसभा चुनाव में 300 किलोमीटर दूर जशपुर से प्रबलप्रताप सिंह जूदेव को बुलाकर मैदान में उतारा गया था। कांग्रेस को लगातार मिल रही ऐसी सीटों पर बीजेपी का फोकस अब बढ़ेगा। क्योंकि, स्मृति ईरानी की बैठकों में ये प्रश्न आया था कि आखिर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ कैसे बना हुआ है। जाहिर है, 2018 में बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई थी मगर कांग्रेस कभी भी 36 सीट से कम नहीं हुई।

# अदम्य, अद्भुत जननायक के सामने सब नतमस्तक

**बस्तर में बंदूक की जगह खेल के मैदान, भय और हिंसा की जगह विश्वास एवं विकास का नया वातावरण : नितिन नवीन**

**जनजातीय समाज का सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि हमारी सरकार का संकल्प : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय**

- **धरमजयगढ़ में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का भव्य आयोजन**
- **मुख्यमंत्री ने पद्मश्री सम्मानित जनजातीय विभूतियों का किया अभिनंदन, जनजातीय नृत्य प्रतियोगिताओं के विजेता दलों को किया पुरस्कृत**



शहर सत्ता/रायपुर। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन अपनी संस्कृति, स्वाभिमान, अधिकारों और मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। जनजातीय गौरव दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि महान जनजातीय नायकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को स्मरण करने तथा उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। राज्यसभा सांसद श्री नितिन नवीन ने आज रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ स्थित ऐतिहासिक दशहरा मैदान में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए यह बात कही।



राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ वीरों, बलिदानियों और समृद्ध जनजातीय संस्कृति की पावन धरती है। श्री नवीन ने कहा कि उनकी हार्दिक इच्छा इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की थी, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण वे उपस्थित नहीं हो सके। श्री नवीन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को भव्य आयोजन के लिए विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय सेवा, समर्पण और जनकल्याण की भावना के साथ प्रदेशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह ने पूरे छत्तीसगढ़ में गौरव और आत्मसम्मान का वातावरण निर्मित किया है।

उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह, तिलका मांझी, बुधु भगत, टंट्या भील और लक्ष्मण नायक सहित देश के महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। श्री नवीन ने कहा कि जनजातीय समाज सदैव भारत की संस्कृति, सभ्यता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता का सशक्त प्रहरी रहा है। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन जीने की जनजातीय परंपरा आज पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के गोंड, उरांव, कंवर, बैगा, कमार, हल्बा, मुरिया और माड़िया सहित सभी जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए कहा कि इन समुदायों की लोककलाएँ, लोकनृत्य, पर्व और परंपराएँ छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान हैं। बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों के माध्यम से जनजातीय संस्कृति को देश-दुनिया में नई पहचान मिल रही है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जनजातीय समाज की बेटी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का विराजमान होना पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और लगभग 24 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान वाली पीएम-जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय बहुल गाँवों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है। नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जनजातीय समाज को विकास योजनाओं का लाभ देने के साथ ही नेतृत्व के अवसर भी प्रदान किए हैं। छत्तीसगढ़ में श्री विष्णु देव साय और ओडिशा में श्री मोहन चरण माझी का मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व करना इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। श्री नवीन ने बस्तर में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रयासों से नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान को निर्णायक सफलताएँ मिली हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ सरकार और वीर सुरक्षाबलों को बधाई दी।

## आदिवासी अस्मिता और स्वतंत्रता: छत्तीसगढ़ के जननायकों का स्वर्णिम इतिहास

**रायपुर। छत्तीसगढ़ की धरती अदम्य जनजातीय साहस के लिए भी इतिहास में अपना अलग महत्व रखती है। यहां के वनवासियों के लिए आजादी केवल सत्ता का बदलाव नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और 'जल, जंगल, जमीन' के अधिकारों की रक्षा का संकल्प थी। 1857 की क्रांति से करीब तीन दशक पहले परलकोट विद्रोह से लेकर भूमकाल और जंगल सत्याग्रह तक, यहां के जननायकों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ शौर्य और बलिदान की मिसाल पेश की।**

### शहीद गैंदसिंह

1857 की क्रांति से लगभग तीन दशक पहलेबस्तर में स्वतंत्रता की पहली चिंगारी सुलग उठी थी। परलकोट विद्रोह के नायक शहीद गैंदसिंह ने मराठा और अंग्रेजी सत्ता के हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित किया था। वर्ष 1824-25 में उनके नेतृत्व में आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों से संघर्ष किया। जनवरी 1825 में अंग्रेजों और मराठों की संयुक्त सेना ने उन्हें बंदी बना लिया और 20 जनवरी,1825 को परलकोट में फांसी दे दी।

### वीर गुण्डाधूर एवं डेबरीधुर

परलकोट के बाद बस्तर में 1910 में भूमकाल विद्रोह की ज्वाला भड़की, जिसके महानायक वीर गुण्डाधूर थे। नेतानार के धुरवा आदिवासी गुण्डाधूर ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, बेगारी और वन अधिकारों के हनन के विरुद्ध आदिवासियों को संगठित किया। अंग्रेजों द्वारा आंदोलन दबाए जाने के बावजूद गुण्डाधूर कभी पकड़े नहीं जा सके। श्रद्धांजलि स्वरूप उनके जन्मस्थान नेतानार से शहीद वीर गुण्डाधूर सेवा डेराकी शुरुआत की गई है। भूमकाल आंदोलन में गुण्डाधुर के सबसे करीबी सहयोगीबोरगाधुर (डेबरीधुर) भी महान क्रांतिकारी थे। गद्दारों के कारण पकड़े जाने पर 29 मार्च,1910 को जगदलपुर के गोल बाजार स्थित इमली पेड़ पर उन्हें फांसी दी गई।

### क्रांतिवीर कंगला मांझी

कांकेर के तेलावट गांव के निवासी और गोंड समुदाय के कंगला मांझी (हीरा सिंह देव) ने वर्ष 1913 से आंदोलन से जुड़कर अनुशासन और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जनजातीय समाज को एकजुट किया। आजादी के बाद भी वे आदिवासियों के उत्थान में सक्रिय रहे और 'आदिवासी किसान सैनिक संगठन' की परंपरा विकसित की। 5 दिसंबर,1984 को उनका निधन हुआ। उनके द्वारा स्थापित 'मांझी सरकार' की परंपरा आज भी जीवित है।

### बंटू धुरवा, सुकदेव पातर एवं रामधीन गोंड

कंगला मांझी से प्रेरित होकर कई नायक आंदोलन में आए। बंटू धुरवा 1910 के भूमकाल आंदोलन से जुड़े थे। वहीं सुकदेव पातर ने झंडा सत्याग्रह के तहत भेलवापानी में अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व किया। शहीद रामधीन गोंड जंगल सत्याग्रह के प्रमुख सेनानी थे।

### संत रामेश्वर गहिरा गुरु

संत गहिरा गुरु (मूल नाम रामेश्वर कंवर) का जन्म 1905 में रायगढ़ के गहिरा ग्राम में हुआ था। वे एक महान संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने शिक्षा, स्वच्छता, नशामुक्ति और सामाजिक अनुशासन के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वर्ष 1943 के बाद उनके सामाजिक कार्यों का विस्तार हुआ। उन्होंने 1953 में कैलाश गुफा आश्रम और संस्कृत शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। 21 नवंबर,1996 को उनके निधन तकउन्होंने वनांचलों में शिक्षा और जनजागरण का अलख जगाया।

### माता राजमोहिनी देवी

सरगुजा के सरसेड़ा में 7 जुलाई,1914 को जन्मीमाता राजमोहिनी देवीमहान समाज सुधारक थीं। उन्होंने जनजातीय समाज में नशाबंदी, स्वच्छता और महिलाओं की जागरूकता के लिए अभियान चलाया। वर्ष 1953 में उन्होंने भटगांव सत्याग्रह का नेतृत्व कियाजिससे समाज में व्यापक बदलाव आया। उनके सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें 1989 में पद्मश्रीसे सम्मानित किया गया। वे महिला सशक्तिकरण की बड़ी प्रतीक थीं। इन जननायकों की गाथाएं छत्तीसगढ़ की जनजातीय विरासत का अमूल्य अंग हैं। जनजातीय गौरव दिवस जैसे आयोजन के माध्यम से इन अमर सेनानियों के बलिदान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं।

## महंगाई का एक और झटका! आज से दूध पैकेट हुई महंगी

**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ में महंगाई के बीच आम लोगों को एक और झटका लगा है। अमूल के बाद अब देवभोग दूध भी महंगा हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ ने दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई दरें 14 नवंबर से लागू हो गई हैं। अब एक लीटर का पैकेट 59 रुपए की जगह 61 रुपए में मिलेगा। वहीं आधा लीटर पैकेट की कीमत 31 रुपए तय की गई है। दूध के दाम बढ़ने से रोजाना खरीदारी करने वाले परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो सकता है। आम उपभोक्ताओं को अब दूध पर पहले से अधिक खर्च करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की ओर से देवभोग दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पहले एक लीटर दूध का पैकेट 59 रुपए में मिलता था, लेकिन अब इसके लिए उपभोक्ताओं को 61 रुपए चुकाने होंगे। यानी प्रति लीटर दूध की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नई दरों के अनुसार आधा लीटर देवभोग दूध के पैकेट की कीमत 31 रुपए कर दी गई है। दूध की नई कीमतें 14 नवंबर से लागू हो चुकी हैं। ऐसे में अब देवभोग दूध खरीदने वाले उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। देश में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। अमूल दूध के दाम बढ़ने के बाद अब देवभोग ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है। पहले से महंगाई का सामना कर रहे आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर इसका असर पड़ सकता है। खासकर रोजाना दूध खरीदने वाले परिवारों को अब हर महीने पहले से ज्यादा खर्च करना होगा।

## पोर्टल चालू, फिर भी राशन से वंचित हो रहे पात्र हितग्राही

**शहर सत्ता/रायपुर।** गरीब परिवारों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तकनीकी उलझन में फंसती नजर आ रही है। राशन वितरण का पोर्टल चालू है, दुकानें भी खुल रही हैं, लेकिन कई पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड सॉफ्टवेयर में इनवेलिड बता रहे हैं। नतीजतन जिन परिवारों को हर महीने चावल, नमक और अन्य खाद्यान्न मिलना चाहिए, उन्हें दुकान पहुंचने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद सामने आ रही इस समस्या ने राशनकार्डधारियों की परेशानी बढ़ा दी है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तकनीकी गड़बड़ी का खामियाजा उन परिवारों को भुगतना पड़ रहा है, जिनकी खाद्य सुरक्षा पूरी तरह सरकारी राशन पर निर्भर है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दायरा काफी बड़ा है। जानकारी के अनुसार धमतरी में करीब 2 लाख 60 हजार राशन कार्ड प्रचलन में हैं। इन कार्डों से 8 लाख 59 हजार से अधिक सदस्य जुड़े हैं।

## बिलासपुर के निकायों में गुपचुप बिछाए गए गैस पाइपलाइन

**शहर सत्ता/रायपुर।** बिलासपुर में गैस पाइपलाइन बिछाने के काम को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। नगर निगम बिलासपुर से लगे नगरीय निकायों में कथित तौर पर बिना वैध अनुमति और मुख्यालय को जानकारी दिए गैस पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा था। इसके लिए सड़कों की खुदाई भी की जा रही थी। मामले की जानकारी सामने आने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यालय ने बिलासपुर सहित संबंधित नगरीय निकायों से सात बिंदुओं पर जानकारी और जवाब मांगा है। इस मामले में स्थानीय निकायों के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। मुख्यालय ने काम से जुड़ी जानकारी के साथ संबंधित निकायों के आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) का नाम, मोबाइल नंबर और आधिकारिक ईमेल आईडी भी मांगी है। इससे साफ है कि विभाग अब केवल पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसियों ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों की भूमिका की भी जानकारी जुटा रहा है।

नगरीय प्रशासन विभाग के पास प्रदेश के पांच बड़े नगर निगमों में सिटी गैस वितरण पाइपलाइन बिछाने की अधिकृत जानकारी दर्ज है। इनमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और अंबिकापुर नगर निगम शामिल हैं। लेकिन बिलासपुर नगर निगम से लगे नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में भी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि संबंधित एजेंसियों ने इस काम की जानकारी नगरीय प्रशासन मुख्यालय को दिए बिना ही खुदाई और पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया। इसी को लेकर विभाग ने संबंधित नगरीय निकायों से स्पष्टीकरण मांगा है।

# कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत आज आएंगे छत्तीसगढ़

## सरगुजा में खदान प्रभावितों से करेंगे चर्चा; 16 से 18 नवंबर तक रहेगा दौरा

**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और सांसद सुखदेव भगत 16 नवंबर से 3 दिवसीय प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिले का दौरा करेंगे। उनका खास फोकस सरगुजा संभाग के कोयला खदान प्रभावित इलाकों पर रहेगा। वे प्रभावित ग्रामीणों और संबंधित पक्षों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तरीय जन चौपाल लगाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सुखदेव भगत 16 नवंबर को झारखंड के लोहरदगा से सड़क मार्ग के जरिए छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। शंख नदी के पास प्रदेश की सीमा पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वे जशपुर, बालाछापर, पतराटोली, कांसाबेल और पत्थलगांव में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पहले दिन का रात्रि विश्राम मैनपाट में प्रस्तावित है।



### साल्ही में कोयला खदान प्रभावितों से करेंगे चर्चा

दौरे के दूसरे दिन यानी 17 नवंबर को सुखदेव भगत मैनपाट से उदयपुर पहुंचेंगे। यहां बूथ स्तरीय जन चौपाल में शामिल होने के बाद ग्राम साल्ही जाएंगे। यहां PEKB, परसा, केते एक्सटेंशन और तारा कोल ब्लॉक से प्रभावित ग्रामीणों और संबंधित हितधारकों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कोयला खनन परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों, ग्रामीणों की समस्याओं और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा होगी। सरगुजा में कोयला खदानों को लेकर लंबे समय से उठ रहे स्थानीय सवालों के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। इसके बाद वे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कांटारोली (मेंद्रा) में जन चौपाल में शामिल होंगे। शाम को अंबिकापुर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे।

### अंबिकापुर में संगठन की बैठक, राजपुर में जन चौपाल

दौरे के अंतिम दिन 18 नवंबर को सुखदेव भगत अंबिकापुर स्थित राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक लेंगे। इसमें अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर विधानसभा क्षेत्रों के संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद वे बलरामपुर जिले के राजपुर पहुंचेंगे। यहां रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को झारखंड के लोहरदगा के लिए रवाना होंगे।

सुखदेव भगत के इस दौरे को कांग्रेस के संगठनात्मक विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जन चौपाल के जरिए वे कार्यकर्ताओं से सीधे फीडबैक लेंगे। वहीं कोयला खदान प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात के जरिए स्थानीय मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। दौरे में संगठन की जमीनी स्थिति और क्षेत्रीय समस्याएं दोनों प्रमुखता से रहेंगी।



## 2028 से पहले आदिवासी अंचलों में सियासी घेराबंदी

**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले ही अभी करीब दो साल दूर हों, लेकिन 2028 की सियासी लड़ाई की तैयारी अभी से तेज होने लगी है। प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दोनों दलों के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता अब आदिवासी बहुल इलाकों में पहुंचकर जनता और संगठन के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा जहां जनजातीय गौरव, आदिवासी नेतृत्व और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के सहारे अपना जनाधार मजबूत रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस जनचौपाल, स्थानीय समस्याओं और खनन प्रभावितों के मुद्दों के जरिए दोबारा भरोसा कायम करने की कोशिश में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 15 नवंबर को धरमजयगढ़ दौरा और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत का 16 से 18 नवंबर तक जशपुर, मैनपाट और सरगुजा क्षेत्र में प्रवास इसी राजनीतिक हलचल का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 15 नवंबर को धरमजयगढ़ पहुंचना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के मुख्य आयोजन के लिए धरमजयगढ़ का चयन आदिवासी बहुल क्षेत्र को पार्टी की प्राथमिकता में रखने का संकेत देता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले वे लंबे समय तक प्रदेश में पार्टी के प्रभारी और सह-प्रभारी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ऐसे में प्रदेश के राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरणों से उनकी पुरानी परिचितता भी इस दौरे को अहम बनाती है।

# बैज ने कहा- आदिवासी विरोधी भाजपा का फर्जी इवेंट

**शहर सत्ता/रायपुर।** भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर पावन स्मरण करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि कुदरत भी नहीं चाहती कि आदिवासी विरोधी भाजपा के फर्जी सरकारी इवेंट में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हों, इसलिए धरमजयगढ़ के कार्यक्रम में नितिन नबीन नहीं पहुंचे। भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा दिए गए "अबुआ दिशुम, अबुआ राज" के संकल्प को सामने रखते हुए, दीपक बैज ने वर्तमान भाजपा सरकार की जनविरोधी, आदिवासी-विरोधी और पूंजीपति-परस्त नीतियों के खिलाफ सवाल उठाये, आज पूरा देश और विशेषकर छत्तीसगढ़ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के संघर्षों को याद कर रहा है, लेकिन विडंबना देखिए कि आज छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के ठीक विपरीत काम कर रही है। आज सत्ता और सेठों का गठजोड़ मिलकर हमारे आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन को उद्योगपतियों के हाथों बेच रहा है। कांग्रेस पार्टी भगवान बिरसा मुंडा के उस 'उलगुलान' क्रांति की प्रेरणा को लेकर इस दमनकारी, बहरी और अंधी भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक आर-पार की लड़ाई लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा सरकार प्रदेशभर में जनजातीय गौरव और आदिवासी कल्याण के झूठे ढोल पीटती है, लेकिन हकीकत यह है कि आज छत्तीसगढ़ के जंगलों को चंद उद्योगपति मित्रों और कारपोरेट घरानों के हवाले किया जा रहा है। जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों को कुचला जा रहा है। आज इस सरकार में आदिवासी वनोपज संग्राहक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पेड़-पौधों की अंधाधुंध कटाई और खनिजों की अंधेरगर्दी से बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल, थल और पर्यावरण संकट में पड़ गया है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज मोदी के मित्र सेठों की तिजौरी भरने के लिए आदिवासियों का खून बहा रहे हैं, नए-नए खदानें खोलने के लिए प्रशासनिक आतंक के जरिए आदिवासियों को उनकी ही पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं।



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने लगान माफी और जल-जंगल-जमीन की लूट के खिलाफ उलगुलान किया था, आज छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार उसी जनविरोधी और पूंजीवादी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनकर हमारे संसाधनों को लुटवा रही है।

## पूर्व भाजपा नेता ने 100 समर्थकों समेत थामा कांग्रेस का हाथ

### भूपेश-बघेल की सभा में कांग्रेस नेता की जेब से 30 हजार पार

**शहर सत्ता/कांकेर/रायपुर।** कांकेर के नरहरपुर में शनिवार को कांग्रेस के 'वोट चोर गद्दी छोड़' कार्यक्रम में पूर्व भाजपा नेता और नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भूपेश नेताम 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। सभा के दौरान कांग्रेस नेता नरेंद्र यादव की जेब से 30 हजार रुपए चोरी हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं ने भूपेश बघेल का स्वागत किया। सभा में उन्होंने धान खरीदी, वोट चोरी और युवाओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने महंगाई और दिवाली पर चना-शक्कर नहीं मिलने समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा।



कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता नरेंद्र यादव की जेब से 30 हजार रुपए चोरी हो गए। घटना नरहरपुर के सुरही की बताई गई है। भीड़ का फायदा उठाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी जेब से रुपए निकाल लिए। इससे पहले 7 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत के कार्यक्रम में भी जेब कटने की शिकायत आई थी। उस दौरान कांग्रेस के एक बड़े नेता समेत कई लोगों की जेब से रुपए चोरी होने की बात सामने आई थी।

## तीन महीने में सीमेंट की बोरी के दाम 80 रुपए तक बढ़े

**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने मकान बनाने वाले लोगों के साथ ही बिल्डरों और ठेकेदारों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में बीते तीन से चार महीनों के दौरान सीमेंट की एक बोरी के दाम में करीब 80 रुपए तक की वृद्धि हो चुकी है। खास बात यह है कि कंपनियों ने कीमतों में एकमुश्त बढ़ोतरी करने के बजाय अलग-अलग समय पर धीरे-धीरे दाम बढ़ाए हैं। अब दिवाली के बाद मकान निर्माण और दूसरे निर्माण कार्यों में तेजी आने के बीच सीमेंट महंगी होने से लोगों का बजट बिगड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहां देश की कुल सीमेंट आवश्यकता का लगभग 20 प्रतिशत उत्पादन होता है। इसके बावजूद प्रदेश के उपभोक्ताओं को दूसरे राज्यों के मुकाबले अधिक कीमत चुकाकर सीमेंट खरीदनी पड़ रही है। जानकारों के मुताबिक, खुदरा बाजार में पिछले तीन-चार महीनों में प्रति बोरी करीब 80 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सरकारी निर्माण कार्यों और बड़े बिल्डरों को सप्लाई किए जाने वाले नॉन-ट्रेड सीमेंट की कीमत भी बढ़ी है।

# किरणदेव बोले- 50 साल केंद्र में रही कांग्रेस लेकिन जनजातीय मंत्रालय नहीं बनाया

## आदिवासी और जनजाति में फर्क कर रही कांग्रेस:दोनों एक ही समाज

**शहर सत्ता/रायपुर।** बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने आदिवासी और जनजाति शब्द को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी और जनजाति दोनों एक ही समाज हैं, फिर इनके बीच फर्क क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस 50-55 साल तक केंद्र की सत्ता में रही, लेकिन उसने जनजाति समाज के विकास के लिए अलग मंत्रालय तक नहीं बनाया। किरणदेव ने यह बातें शनिवार को रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं।



### कांग्रेस बताए, जनजाति समाज के लिए क्या किया?

किरण सिंह देव ने कहा कि, बीजेपी सरकार जनजाति समाज के विकास और उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार की एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं इस समाज के विकास के लिए चलाई जा रही हैं। इनमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी शामिल है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि इतने लंबे समय तक केंद्र में सरकार रहने के बावजूद उसने जनजाति समाज के विकास के लिए क्या किया और कौन-सी योजनाएं शुरू कीं।

### भाषा-बोली अलग, लेकिन समाज एक ही है

सिंहदेव ने आदिवासी और जनजाति शब्दों के बीच अंतर किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बस्तर में ही हर 20-25 किलोमीटर पर अलग-अलग जनजातीय समुदाय मिलते हैं। उनकी भाषा, बोली, खान-पान और पहनावा अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सभी जनजाति समाज का हिस्सा हैं। ऐसे में आदिवासी और जनजाति को अलग-अलग बताकर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आदिवासी समाज के लोग भी जनजाति समाज में ही आते हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश और प्रदेश के जनजातीय नायकों का सम्मान किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से याद किया जाता है। इसी तरह बस्तर के गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे नायकों ने भी देश और समाज के लिए योगदान दिया है। इन वीरों के सम्मान और उनके योगदान को याद करने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

**राज्यपाल रमेन डेका ने कर्मचारियों को दीपावली उपहार भेंट किए**

# लोक भवन में दीपावली मिलन समारोह आयोजित

**शहर सत्ता/रायपुर।** लोक भवन में आज राज्यपाल श्री रमेन डेका की उपस्थिति में दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। समारोह में लोक भवन के अधिकारियों-कर्मचारियों और उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर लोक भवन परिवार के सदस्यों और उनके बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गीत-संगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समारोह में उत्साह और उमंग का वातावरण बना दिया।



समारोह के दौरान लोक भवन के कर्मचारियों और उनके परिजनों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने भी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। राज्यपाल ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने लोक भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दीपावली के उपहार भी भेंट किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने सत्यम योग संस्थान के सदस्यों को भी सम्मानित किया। योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने और उसके माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देने के लिए उन्होंने संस्थान के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

राज्यपाल रमेन डेका ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व आपसी प्रेम, सद्भाव, सहयोग और भाईचारे का संदेश देता है। ऐसे आयोजन सभी को एक-दूसरे के साथ जुड़ने और पारिवारिक आत्मीयता के साथ त्योहार मनाने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने समारोह में उत्साहपूर्वक भागीदारी के लिए लोक भवन परिवार के सभी सदस्यों की सराहना की। समारोह में राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे सहित लोक भवन के अधिकारी-कर्मचारी एवं उनके परिजन उपस्थित थे।

## फसल बीमा योजना में भर्ती का इंटरव्यू पोस्टपोन

**शहर सत्ता/रायपुर।** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत राज्य में योजना के संचालन और निगरानी से जुड़े कामों के लिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया फिलहाल टल गई है। स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (SPMU) में ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टेम्परेरी नियुक्ति के लिए 17 नवंबर को प्रस्तावित वॉक-इन-इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिया गया है। कृषि संचालनालय ने अपरिहार्य कारणों से यह फैसला लिया है। इस भर्ती के जरिए राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट में मानव संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञों को जोड़ा जाना था। SPMU का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की निगरानी, संबंधित विभागों के बीच समन्वय और योजना से जुड़े तकनीकी कामों में सहयोग करना है। इन पदों पर नियुक्ति अस्थायी आधार पर की जानी थी। कृषि संचालनालय की ओर से जारी सूचना में इंटरव्यू पोस्टपोन करने की जानकारी दी गई है। हालांकि, नई तारीख और आगे की भर्ती प्रक्रिया को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की अगली तारीख के लिए कृषि संचालनालय की आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी होगी।

## छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में 16°C से नीचे तापमान

**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। राज्य के 10 जिलों में रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। सरगुजा जिले का अंबिकापुर 11.4 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। राजधानी रायपुर में भी सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के उत्तरी और मध्य इलाकों में सर्द हवाओं ने दस्तक दे दी है। सरगुजा संभाग में रातें सबसे ज्यादा सर्द हो रही हैं। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम होकर 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बलरामपुर-रामानुजगंज में पारा 13.4 डिग्री और बालोद में 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा। दुर्ग में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। इसके अलावा बेमेतरा में 14.9 डिग्री और कबीरधाम में 15 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। बस्तर में 15.2 डिग्री, मुंगेली और सूरजपुर में 15.5 डिग्री पारा दर्ज किया गया। कोरबा में 15.9 डिग्री और बिलासपुर में 17.4 डिग्री तापमान रहा। राजधानी रायपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक है। माना एयरपोर्ट इलाके में रात का तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज रायपुर का आसमान साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है।

## घर पर मिला लॉ छात्रा का शव, सुसाइड नोट पर लिखा पासवर्ड

**शहर सत्ता/रायपुर।** दिल्ली में रहकर एलएलबी अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही छात्रा टी. त्रिशा (23) की आत्महत्या के मामले में शुक्रवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। परिजन ने रिसाली मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने मौके से एक पन्ने का सुसाइड नोट जब्त किया है, जिसमें छात्रा ने एक युवक से प्रेम संबंध टूटने से आहत होकर यह कदम उठाने की बात लिखी है। साथ ही उसने अपने मोबाइल और गूगल-पे के पासवर्ड भी दर्ज किए हैं। नेवई थाना टीआई अनिल साहू ने बताया कि रिसाली लक्ष्मी नगर फेज-1 निवासी डिलेश्वर राव की पुत्री टी. त्रिशा दिल्ली के एक कॉलेज से एलएलबी फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। वह दिवाली की छुट्टियों में घर आई थी। परिवार में माता-पिता के अलावा दो बहनें और एक भाई हैं। बुधवार रात सभी ने साथ भोजन किया, जिसके बाद रात करीब 12 बजे त्रिशा अपने कमरे में सोने चली गई। गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे जब परिजन ने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। खिड़की से झांकने पर वह सीलिंग फैन से फंदे पर लटकी दिखाई दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। बेटी के इस आत्मघाती कदम से पूरा परिवार सदमे में है। टीआई ने बताया कि घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए।

# राजेंद्र नगर फूड पार्क में आग, 2 सिलेंडर ब्लास्ट

## आधा दर्जन दुकानें चपेट में आईं, शॉर्ट सर्किट बनी वजह






**शहर सत्ता/रायपुर।** रायपुर स्थित राजेंद्र नगर की चौपाटी में रविवार दोपहर को भड़की भीषण आग की चपेट में आकर 5 से 6 दुकानें पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गईं. इस आगजनी की घटना से दुकानदारों को लाखों रुपये की संपत्ति का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि दुकानों के भीतर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया. चौपाटी में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकानें संचालित होती हैं, जो इस हादसे का शिकार बनीं.हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं और आग पर नियंत्रण पाने के लिए घंटों तक मशक्कत की.

आग बुझाने के अभियान के दौरान ही एक दुकान में रखे सिलिंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे संबंधित दुकान को अत्यधिक क्षति पहुंची है. हालांकि, दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत करते हुए आग को आसपास की अन्य दुकानों तक फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया.

घटना के संबंध में जोन अध्यक्ष सचिन मेघानी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि आग लगने का पता चलते ही बिना देरी किए पुलिस को सूचित कर दिया गया था, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि वे जल्द ही आधा दर्जन दुकानों में फैल गईं. फिलहाल, इस अग्निकांड के पीछे के सटीक कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, परंतु शुरुआती अनुमान के तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है.



## तिल्दा के रायखेड़ा थर्मल-प्लांट में हादसा, एक मजदूर की मौत

**शहर सत्ता/रायपुर।** रायपुर जिले के तिल्दा स्थित रायखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन में एक मजदूर की मौत हो गई है। प्लांट में काम करने के दौरान हुए हादसे में बिहार के रहने वाले 45 साल के जिनिसलाल यादव की मौत हो गई। वे बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर का रहने वाला था। मजदूर संघ ने लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि, काम के दौरान हुक नहीं लगाया था। रायपुर ग्रामीण सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि, काम के दौरान जरूरी हुक नहीं लगाया गया था, जिसके चलते मजदूर की जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और सुरक्षा में कहां चूक हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

### पहले भी हो चुके हैं हादसे

**अगस्त 2026 :** प्लांट परिसर में कर्मचारी केशव कुमार महिलांगे की मौत हुई थी। शुरुआती जानकारी में भारी वाहन की चपेट में आने की आशंका जताई गई थी। इसके बाद परिजनों ने मुआवजे और शव सुपुर्दगी को लेकर प्लांट गेट पर प्रदर्शन किया था।

**अगस्त 2026 :** केशव कुमार महिलांगे की मौत से करीब तीन दिन पहले इसी प्लांट में हुए हादसे में पांच मजदूर घायल हुए थे।

**अगस्त 2014 :** रायखेड़ा में निर्माणाधीन पावर प्लांट में काम करते समय 25 साल के मजदूर सुनील राम की करंट लगने से मौत हो गई थी। वह बिहार का रहने वाला था।

# सोलर वेलफेयर एसोसिएशन के दिवाली मिलन में पहुंचे बृजमोहन अग्रवाल



**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन के दिवाली मिलन समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशभर से आए सोलर कारोबारियों, डीलरों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं और सभी को शुभकामनाएं दीं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सोलर ऊर्जा अब केवल बिजली का विकल्प नहीं है, बल्कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का आधार बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिजली के भंडारण (एनर्जी स्टोरेज), आधुनिक बैटरी और नई तकनीक की भूमिका और बढ़ेगी। सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों और युवाओं के लिए रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा होंगे।

### लिथियम के भंडार मिलने से छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगी संभावनाएं

सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह गर्व की बात है कि प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। इससे आने वाले समय में बैटरी बनाने और बिजली के भंडारण के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी।

### चैंबर अध्यक्ष समेत पदाधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी, छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष ललित जयसिंघ समेत प्रदेशभर से आए एसोसिएशन के प्रतिनिधि, पदाधिकारी और सोलर कारोबारी मौजूद रहे। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने मां लक्ष्मी से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

# पेंशनर 30 नवंबर तक बनवा सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट



**शहर सत्ता/रायपुर।** रेलवे के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने मंडल के 7 स्टेशनों पर इसके लिए शिविर लगाए हैं। यह अभियान 2 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 30 नवंबर 2026 तक चलेगा। शिविरों में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रमाण पत्र बनवाए जा सकते हैं।

### अब तक 482 प्रमाण पत्र बने

रायपुर रेल मंडल में 13 नवंबर तक 482 डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए जा चुके हैं। मंडल के मुताबिक, यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। पेंशनभोगी तय तारीख पर संबंधित स्टेशन पहुंचकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए कार्मिक विभाग ने कल्याण निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर 30 नवंबर को शिविर लगेगा। दुर्ग स्टेशन पर 6 और 7 नवंबर को शिविर आयोजित हो चुका है। बीएमवाई में 11 से 14 नवंबर और फिर 25 व 26 नवंबर को शिविर लगेगा। भिलाई स्टेशन पर 16 से 18 नवंबर तक, भाटापारा और तिल्दा-नेवरा स्टेशन पर 19 से 21 नवंबर और 27 से 28 नवंबर तक शिविर आयोजित किए जाएंगे। दल्लीराजहरा स्टेशन पर 23 और 24 नवंबर को यह सुविधा मिलेगी।

### डिजिटल तरीके से जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के जरिए पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इससे पेंशन से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया पूरी करना आसान होगा। उन्हें हर बार कागजी प्रमाण पत्र जमा करने की परेशानी से भी राहत मिलेगी।

# DRM ऑफिस का कर्मचारी बनकर किया फोन

## PPO नंबर अपडेट कराने के नाम पर रिटायर्ड रेलकर्मी से 7.49 लाख की ठगी



**शररसत्ता/रायपुर।** रायपुर में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। यहां एक अज्ञात ठग ने खुद को रेलवे के DRM ऑफिस का कर्मचारी बताकर रिटायर्ड रेलकर्मी को फोन किया और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर रिवाइज कराने का झांसा देकर उनके बैंक खाते से 7 लाख 49 हजार 783 रुपये पार कर दिए। आरोपी ने रिटायर्ड कर्मचारी को भरोसे में लेकर उनके मोबाइल में रेलवे का HRMS ऐप और बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा एक लिंक डाउनलोड करवाया था। इसके कुछ ही देर बाद खाते से रकम ऑनलाइन ट्रांसफर हो गई। मामले में डीडी नगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल नंबर और जिन बैंक खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई है, उनकी जानकारी जुटा रही है।

पुलिस के मुताबिक, रायपुरा स्थित विकास विहार कॉलोनी निवासी श्रद्धा जोल्दे (52) ने शनिवार रात डीडी नगर थाने पहुंचकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 11 अक्टूबर की आधी रात उनके पति राजू जोल्दे के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को DRM ऑफिस का कर्मचारी बताया। उसने राजू जोल्दे से कहा कि रेलवे से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के एक साल बाद अपना PPO नंबर रिवाइज कराना पड़ता है। आरोपी ने इस प्रक्रिया को जरूरी बताते हुए उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया।

### HRMS ऐप और बैंक का लिंक डाउनलोड करवाया

ठग ने रिटायर्ड रेलकर्मी को PPO नंबर अपडेट कराने की प्रक्रिया पूरी करने का झांसा दिया। इसके लिए उसने राजू जोल्दे के मोबाइल में रेलवे का HRMS ऐप और बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित एक लिंक डाउनलोड करवाया। आरोपी ने इस पूरी प्रक्रिया को आधिकारिक काम बताकर उनका भरोसा जीत लिया। राजू जोल्दे को लगा कि रेलवे की पेंशन संबंधी जानकारी अपडेट करने के लिए यह जरूरी प्रक्रिया है। इसी वजह से उन्होंने फोन करने वाले की बात मान ली। हालांकि, मोबाइल पर ऐप और लिंक डाउनलोड करने के कुछ ही समय बाद उनके बैंक खाते से बड़ी रकम निकल गई।

### खाते से 7 लाख 49 हजार 783 रुपये हुए ट्रांसफर

PPO नंबर रिवाइज कराने के नाम पर शुरू हुई बातचीत का नतीजा यह हुआ कि राजू जोल्दे के बैंक खाते से 7 लाख 49 हजार 783 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए। जब परिवार को खाते से रकम निकलने की जानकारी मिली, तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद श्रद्धा जोल्दे ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित परिवार के मुताबिक, आरोपी ने रेलवे कर्मचारी बनकर पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया का हवाला दिया था और इसी बहाने उनके साथ धोखाधड़ी की। शिकायत मिलने के बाद डीडी नगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

# रेल मंडल में कर्मचारियों ने सैलरी में कटौती के लगाए आरोप




**शररसत्ता/रायपुर।** यात्रियों को स्वच्छ सफर देने वाले रेल सफाईकर्मियों के साथ ही आर्थिक शोषण का मामला सामने आया है। रायपुर रेल मंडल में ट्रेनों की साफ-सफाई और पानी की व्यवस्था संभालने वाली ठेका कंपनी 'किंग एक्सपर्ट्स इन सिक्योरिटी सॉल्यूशन' पर कर्मचारियों के वेतन में कथित कटौती और एटीएम कार्ड अपने पास रखने के गंभीर आरोप लगे हैं। कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें हर महीने 18 से 20 हजार रुपए वेतन मिलना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में केवल 10 हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं। बाकी रकम बैंक खाते से निकाल ली जाती है। कर्मचारियों ने इस मामले में श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पीड़ित कर्मचारियों के मुताबिक, पिछले 3 से 4 वर्षों से कंपनी ट्रेनों में सफाई और पानी की व्यवस्था का काम संभाल रही है। इस दौरान कर्मचारियों को निर्धारित वेतन के मुकाबले काफी कम रकम दी जा रही है। उनका आरोप है कि हर महीने 18 से 20 हजार रुपए वेतन खाते में जमा होता है, लेकिन उन्हें नकद के रूप में केवल 10 हजार रुपए ही मिलते हैं। इस तरह हर कर्मचारी के वेतन से 8 से 10 हजार रुपए तक की कथित कटौती की जा रही है।

### कर्मचारियों के ATM कार्ड रखने का भी आरोप

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप कर्मचारियों के बैंक खातों और एटीएम कार्ड से जुड़ा है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने उनके एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए हैं। वेतन खाते में जमा होने के बाद एटीएम के जरिए अतिरिक्त रकम निकाल ली जाती है और कर्मचारियों को केवल 10 हजार रुपए दिए जाते हैं। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह कर्मचारियों के आर्थिक अधिकारों और वेतन भुगतान की पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर मामला है। लंबे समय से कथित वेतन कटौती और अन्य समस्याओं का सामना कर रहे सफाईकर्मियों ने अब एकजुट होकर विरोध शुरू कर दिया है। दर्जनों कर्मचारियों ने 13 सूत्रीय मांगों के साथ श्रम न्यायालय में शिकायत की है। उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम मजदूरी के नियमों के अनुसार पूरा वेतन, एटीएम कार्ड वापस करना, नियुक्ति पत्र जारी करना, सवेतन अवकाश, मेडिकल जांच और नौकरी की सुरक्षा शामिल हैं।

## संपादकीय



सुकांत राजपूत

# नहीं थम रही धरती की तपिश

दुनिया भर में इस बात पर सहमति है कि अगर बढ़ते वैश्विक ताप के मसले पर जल्दी ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो व्यापक स्तर पर इसके खमियाजे किसी न किसी रूप में सभी देशों को उठाने पड़ेंगे। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी करने वाले सभी देश इस पर गहरी चिंता जताते हैं। मगर हकीकत यह है कि बीते कई दशकों से लगातार वैश्विक ताप में इजाफे के कारणों और हल के उपायों पर सिर्फ चर्चा ही होती रही है।

उन पर अमल का सवाल आते ही अलग-अलग कारणों का हवाला देकर ज्यादातर देश अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। खासतौर पर जिन विकसित या समृद्ध देशों को सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वे अपनी जवाबदेही को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखते और दुनिया का तापमान बढ़ने की जिम्मेदारी विकासशील देशों पर थोप देते हैं। सवाल है कि अगर विकसित देशों का यही रवैया कायम रहा, तो जलवायु परिवर्तन और उसकी वजह से खड़ी होने वाली स्थितियां कहां तक जाएंगी!

गौरतलब है कि तुर्किये के अंताल्या शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 'सीओपी 31' में बुधवार को एक बार फिर इस मुद्दे पर औपचारिक बातचीत शुरू हुई। इस बार की वार्ता के केंद्र में मुख्य रूप से पिछले साल भर में आई विनाशकारी बाढ़, लू और जलवायु से जुड़ी अन्य आपदाएं हैं। सम्मेलन में शामिल देश वैश्विक ताप को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

मगर इन प्रयासों की सीमा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अमेरिका और चीन सहित कई वैसे देश 'सीओपी 31' में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में हुए सम्मेलन में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने को लेकर एक लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति संभव नहीं हो सकी है और यह मुद्दा आज भी अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में चिंता का मुख्य विषय बना हुआ है। हालत यह है कि धरती का तापमान अब 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करना लगभग तय माना जा रहा है।

जब वैश्विक ताप की वजह से कहीं बेलगाम बाढ़, तो कहीं टूटते हिमनद या लू जैसे हालात के रूप में दुनिया भर में होने वाली तबाही सामने है, तब भी विकसित देशों के बीच इस मसले पर एक विचित्र उदासीनता कायम है। जलवायु परिवर्तन से उपजे संकट को केंद्र में रख कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन भले होते रहते हैं, लेकिन उसका अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है।एक नई रिपोर्ट में दी गई चेतावनी से समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि देशों के जलवायु वादों और वास्तव में होने वाली उत्सर्जन कटौती के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। जबकि स्थिति पर काबू पाने के लिए दुनिया को कार्बन उत्सर्जन में छह फीसद तक की कटौती करना जरूरी होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे लेकर विकसित देश गंभीर नहीं हैं।

दूसरी ओर, गरीब और विकासशील देशों के सामने सीमित संसाधनों के बीच अपने दम पर जलवायु संकट का सामना करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यावहारिक उपायों के संदर्भ में विकसित देशों से भारत की यह मांग बिल्कुल उचित है कि वे पेरिस जलवायु समझौते के मुताबिक विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराएं।

# दीवाली 2026: लिफाफे का अवसान तोहफों का नया संविधान..!




**कॉलम - खुरचन**

द्वारा- हरिदास

दीपावली साल में एक बार आती है, लेकिन ख़बरनवीसों और जनप्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता का आदान-प्रदान पूरे साल चलता रहता है। दीपावली पर इस आत्मीयता का सार्वजनिक प्रदर्शन होता है। आमंत्रण का घंटों इंतजार करने के बाद मिठाई के डिब्बे खुलते हैं, मुस्कानें खिलती हैं और लिफाफों का लेन-देन लोकतंत्र की उस महान परंपरा को आगे बढ़ाता है, जिसके बारे में सब जानते हैं, मगर कोई बोलता नहीं।दीवाली का लिफाफा भारतीय लोकतंत्र की अद्भुत देन है। यह ऐसी पारदर्शी अपारदर्शिता है, जिसमें भीतर क्या है, यह जानने के लिए खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। देने वाला समझता है, लेने वाला समझता है और आसपास खड़ा तीसरा आदमी भी समझ जाता है।

लेकिन इस दीवाली यानी 2026 के दीपोत्सव में उपहार शास्त्र और सम्मान के अर्थशास्त्र में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला। कहीं से लिफाफे की जगह चावल का उपहार तो कहीं सरसों का तेल मिला, कहीं मिलेट का पैकेट और कहीं कंबल। मिठाई के साथ घरेलू जरूरतों का पूरा पैकेज। आयोजकों ने मानो ख़बरनवीसों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कराया हो और निष्कर्ष निकाला हो कि इनकी जेब भले खाली हो, लेकिन रसोई भी खाली है।

ख़बरनवीस और परिष्कर्ता आमंत्रण पर पहुंचे थे। उम्मीद थी कि मिठाई के साथ कोई लिफाफा भी मिलेगा। लेकिन जब हाथ में चावल का पैकेट थमाया गया तो चेहरे पर वह मुस्कान आ गई, जो किसी सरकारी योजना का लाभार्थी अपना नाम सूची में देखकर देता है। कुछ ख़बरनवीसों ने पैकेट को उलट-पलटकर देखा। शायद भीतर कोई लिफाफा छिपा हो। लेकिन आयोजकों ने इस बार पारदर्शिता की नई परिभाषा गढ़ दी थी। जो दिख रहा है, वही मिलेगा। कोई रहस्य नहीं, कोई रोमांच नहीं।

धान के कटोरे में रहने वाले ख़बरनवीसों को चावल देना अपने आप में दूरदर्शी फैसला है। आखिर खबरें लिखने से पेट नहीं भरता। धान का कटोरा कहलाने वाले प्रदेश में चावल खरीदना भी अब आसान नहीं रहा। आयोजकों ने सोचा होगा कि ख़बरनवीसों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी लोकतांत्रिक दायित्व है। सरसों का तेल भी दिया गया। यह तय नहीं हो पाया कि इसका उपयोग सब्जी बनाने में होगा, अचार डालने में होगा या ख़बरनवीसों की मालिश में। कुछ ख़बरनवीसों ने तो इसे अपनी कलम की धार तेज करने का सरकारी इंतजाम समझ लिया। हालांकि एक अनुभवी ख़बरनवीस ने सवाल उठाया कि तेल कलम में डालना है या खबरों में?

कंबल की सौगात भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। सर्दियां आने वाली हैं। ख़बरनवीसों का जीवन भी कोई आरामदेह नहीं होता। रात में दफ्तर से से लौटना पड़ता है, कभी किसी नेता के बयान के पीछे भागना पड़ता है, कभी किसी अधिकारी के दरवाजे पर घंटों खड़ा रहना पड़ता है। रात दो बजे मोबाइल पर खबर अपडेट करनी पड़ती है। ऐसे में कंबल देना मानवीय संवेदना का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब ख़बरनवीस खबरों के पीछे भागते हुए ठंड से नहीं कांपेंगे। कंबल ओढ़कर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। हालांकि एक ख़बरनवीस ने धीरे से पूछा कि कंबल ओढ़कर अगर किसी भ्रष्टाचार की खबर दबानी पड़े तो क्या उसे भी ओढ़कर सो जाएं? सवाल अच्छा था, लेकिन समारोह में ऐसे सवाल पूछने की परंपरा नहीं थी।

इस पूरे घटनाक्रम को केवल उपहारों का बदलाव समझना भूल होगी। दरअसल, यह तोहफे के अर्थशास्त्र का नया अध्याय है। इसमें भावनाओं की पैकिंग होती है, आत्मीयता की ब्रांडिंग होती है और राजनीतिक संबंधों की मार्केटिंग। लिफाफा नकद अर्थव्यवस्था का प्रतीक था। उसमें मुद्रा थी और मुद्रा में विकल्प। चावल, तेल और कंबल वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था के प्रतिनिधि हैं। अब आयोजक बाजार से सामान खरीदकर सीधे ख़बरनवीस के घर की अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहे हैं।

यह अर्थव्यवस्था भी बड़ी दिलचस्प है। देने वाले के लिए तोहफा एक खर्च है, लेने वाले के लिए बचत और देखने वाले के लिए चर्चा। लेकिन राजनीति के लिए यह एक निवेश है, जिसका प्रतिफल कभी आत्मीयता, कभी प्रशंसा और कभी कम से कम असुविधाजनक सवालों की अनुपस्थिति के रूप में मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

लिफाफे में एक खतरा था। उसकी रकम देखकर लोग अनुमान लगा सकते थे। सामान में यह सुविधा है कि उसकी कीमत बाजार तय करता है और सम्मान की कीमत आयोजक। पांच किलो चावल देकर भी कोई कह सकता है कि हमने दिल खोलकर सम्मान किया है। दो लीटर तेल देकर आत्मीयता की गहराई नापी जा सकती है। कंबल की मोटाई से रिश्तों की गर्माहट का प्रमाणपत्र भी जारी किया जा सकता है।

इस अर्थशास्त्र में एक और विशेषता है। नकद उपहार पर सवाल उठ सकता है, लेकिन राशन पर सवाल उठाना कठिन है। चावल मिला है तो खाद्य सुरक्षा, तेल मिला है तो पोषण, मिलेट मिला है तो स्वास्थ्य और कंबल मिला है तो सामाजिक सुरक्षा। इस तरह एक ही आयोजन में पत्रकार मिलन, जनकल्याण, पोषण अभियान और शीतकालीन राहत योजना का समन्वय हो गया।

आयोजक भी खुश, ख़बरनवीस भी सामान लेकर घर पहुंचे और अर्थशास्त्रियों को अध्ययन का नया विषय मिल गया।

यह भी गजब का आर्थिक सुधार है। पहले सम्मान की राशि दी जाती थी, अब सम्मान की वस्तुएं दी जा रही हैं। पहले ख़बरनवीस अपनी जरूरत का सामान खुद चुनता था, अब आयोजक उसकी जरूरतें तय कर रहे हैं। ख़बरनवीस को यह भी बताने की जरूरत नहीं कि घर में क्या कमी है। आयोजक ने पहले ही तय कर लिया है कि उसके घर में चावल की कमी है, तेल की कमी है और ठंड में कंबल की कमी है।

बस एक चीज की कमी पर किसी का ध्यान नहीं गया—पत्रकारिता में स्वतंत्रता की कमी।

शायद यह अगली दीपावली के पैकेज में शामिल की जाएगी।

शहर सत्ता की तरफ से दीपोत्सव 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं...

# चीन पर निर्भरता घटाने की हो तैयारी



गत नौ नवंबर को चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एलान किया कि कुछ निर्यात प्रतिबंधों पर लगी अंतरिम रोक की अवधि दो महीने बढ़ाई जा रही है। यानी 10 जनवरी तक के लिए उसने निर्यात प्रतिबंध के निर्णय को टाल दिया है। इसका अर्थ है कि दुनिया भर के उद्योगों को दो महीने की तात्कालिक राहत मिल गई। जर्मनी, जापान एवं भारत के कारखानों से लेकर सामरिक तैयारियों में लगे तमाम देशों के लिए यह बयान किसी बड़ी रणनीतिक रियायत से कम नहीं। चीन का यह फैसला विश्व में वाहन निर्माण और रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों की किस्मत तय करने वाला था कि अगले दो महीनों तक वे सुचारु रूप से चलती रहेंगी या ठप पड़ जाएंगी?

रेयर अर्थ 17 धातुओं का एक समूह है। हालांकि नाम के अर्थ की कसौटी पर देखा जाए तो ये तत्व उतने दुर्लभ भी नहीं। इन्हें दुर्लभ बनाती है कि इन्हें पृथक करने और रिफाइनिंग यानी परिष्कृत करने की क्षमता। यह प्रक्रिया बेहद जटिल, प्रदूषणकारी और खर्चीली है। परिष्कृत रेयर अर्थ तत्वों का उपयोग छोटे, बेहद शक्तिशाली मैग्नेट या चुंबक बनाने में होता है। यही मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों, एयर टर्बाइनों, स्मार्टफोन, हार्ड ड्राइव, लड़ाकू विमानों और गाइडेड मिसाइलों के भीतर लगे होते हैं। इनकी महत्ता इससे समझी जा सकती कि अगर एक मामूली से वजन का मैग्नेट समय पर न पहुंचे तो वह बड़े से बड़े कारखाने की चाल को रोक सकता है। रेयर अर्थ की समूची आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का पूरी तरह से वर्चस्व है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आइईए के अनुसार 2024 में मैग्नेट निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रेयर अर्थ खनिजों के खनन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत, परिष्कृत सामग्री में करीब 91 प्रतिशत और तैयार मैग्नेट के उत्पादन में लगभग 94 प्रतिशत थी। डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसी भारी दुर्लभ धातुओं के मामले में तो चीन की हिस्सेदारी लगभग शत प्रतिशत है। ये धातुएं मैग्नेट को उच्च तापमान पर भी प्रभावी एवं सक्षम बनाए रखती हैं।

रेयर अर्थ भले ही भारत समेत कई देशों में हों, लेकिन परिशोधन के मामले में ऐसा नहीं है और यही सबसे बड़ा रणनीतिक अवरोध है। आखिर यह स्थिति बनी कैसे? अप्रैल 2025 में चीन ने कुछ चुनिंदा रेयर अर्थ खनिजों पर निर्यात नियंत्रण लागू करते हुए उनकी आपूर्ति के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। अक्टूबर 2025 में उसने इन पाबंदियों का दायरा अप्रत्याशित रूप से बढ़ाते हुए इसमें औद्योगिक उपयोग में काम आने वाले हीरे और लीथियम बैट्री तकनीक को भी शामिल कर लिया। इसके अगले माह नौ नवंबर को दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सहमति के बाद इन पाबंदियों को एक साल के लिए टाल दिया गया। नौ नवंबर की घोषणा उसी अंतरिम रोक को दो महीने और आगे बढ़ाती है, क्योंकि वाशिंगटन और बीजिंग एक स्थायी व्यापार समझौते के लिए बात कर रहे हैं। यह ध्यान रहे कि नियंत्रण के निलंबन को केवल टाला गया है, न कि उन्हें समाप्त किया गया है। ये प्रतिबंध आज भी चीनी नियमावली में दर्ज हैं, जिन्हें कभी भी दोबारा लागू किया जा सकता है।

चीन के यह सब करने के पीछे तीन कारण गिनाए जाते हैं। पहला, व्यापार वार्ताओं में अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाना। वैसे तो लाइसेंस की अनिवार्यता कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं, लेकिन जब वैश्विक आपूर्ति में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी वाला कोई देश ऐसी पहल करे तो वह समस्त आपूर्ति को ठप करने के लिए काफी है। दूसरा, सेमीकंडक्टर और अत्याधुनिक तकनीक पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना। तीसरा, अपनी दीर्घकालिक औद्योगिक रणनीति के तहत कदम उठाना। चीन ने चार दशकों तक रिफाइनिंग में भारी निवेश किया, पर्यावरणीय प्रदूषण को झेला और प्रतिस्पर्धियों से बेहद कम कीमतों पर उत्पाद बेचे, ताकि दुनिया में कहीं भी इसका वैकल्पिक उत्पादन तंत्र विकसित न हो और यदि कोई देश ऐसा करे तो उसके लिए यह घाटे का सौदा बन जाए। एक चौथा कारण भी है कि विश्व याद रखे कि इस खेल की कमान किसके पास है। 2010 में एक क्षेत्रीय विवाद के दौरान चीन ने जापान को किए जाने वाले रेयर अर्थ के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी।

चीन जब चाहे, तब किसी को भी सबक सिखा सकता है। वैसे तो पूरी दुनिया के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं, लेकिन भारत के लिए इसका असर एकदम सीधा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 53,748 टन रेयर अर्थ मैग्नेट का आयात किया, जिसमें से 90 प्रतिशत से अधिक चीन से आया। हमारे इलेक्ट्रिक वाहन, पवन ऊर्जा के लक्ष्य और इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण की महत्वाकांक्षाएं इसी आयात पर निर्भर हैं। 69 लाख टन के साथ भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है। इस मोर्चे पर वह केवल चीन एवं ब्राजील से ही पीछे है। इसके बावजूद 2024 में भारत ने महज 2,900 टन का उत्पादन किया, जो वैश्विक उत्पादन के एक प्रतिशत से भी कम है। हम खनन बहुत कम करते हैं और रिफाइनिंग उससे भी कम।

यह सही है कि सरकार ने कुछ कदम बढ़ाए हैं। उसने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है और इसके लिए संसाधनों का आवंटन भी किया जा रहा है, लेकिन केवल इतने भर से बात नहीं बनने वाली। सब कुछ घर पर बना लेना ही आत्मनिर्भरता नहीं है। यह न तो बहुत टिकाऊ विकल्प है और न ही सबसे समझदारी की बात। इसलिए भारत को एक रणनीति पर काम करना होगा। हमें ऐसी वस्तुओं की ओर देखना होगा, जिन्हें कई देश बेचते हैं और जिन्हें हम सीधे बाजार से खरीद सकते हैं। जहां भी अयस्क के दोहन और उनके उत्पादन की संभावनाएं मौजूद हों, वहां घरेलू क्षमता विकसित करने के लिए सब्सिडी पूरी तरह तर्कसंगत है। रेयर अर्थ की रिफाइनिंग और मैग्नेट निर्माण इसी श्रेणी में आते हैं। याद रहे कि चीन ने अभी 10 जनवरी तक की मोहलत दी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठा जाए। यह रियायत कभी भी खत्म हो सकती है। इसलिए अगर समय मिला है तो उसे गंवाए बिना मजबूत बुनियाद रखी जानी चाहिए।



## बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना?

**नई दिल्ली।** बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर में अपने देश लौट सकती हैं. अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत आईं शेख हसीना ने अब बांग्लादेश वापसी की इच्छा जताई है. बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत भी उनकी वापसी के रास्ते पर सहमत है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें चाहता है. भारत की मांग है कि शेख हसीना की सुरक्षा की पूरी गारंटी हो और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले. रिपोर्ट में भारतीय विदेश मंत्रालय और सैन्य प्रतिष्ठान के अज्ञात सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है. हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया. बीबीसी बांग्ला ने गुरुवार (12 नवंबर) को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बताया कि नई दिल्ली पिछले कुछ समय से शेख हसीना की निर्वासन से वापसी का रास्ता तैयार करने में जुटी है. इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित हो और उन्हें न्याय मिलने का अवसर भी मिले. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है और न ही इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है.

## मियामी रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान

**नई दिल्ली।** अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार (14 नवंबर 2026) की रात दो विमान आपस में टकरा गए. हादसे में UPS का बोइंग 767 कार्गो विमान और कोपा एयरलाइंन्स का बोइंग 737 पैसेंजर विमान शामिल थे. इस टक्कर में दो लोगों को मामूली चोटें आईं. दोनों को मौके पर ही इलाज दिया गया और अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि जब विमानरनवे पर चल रहे थे तब कोपा एयरलाइंस के बोइंग 737 के विंगटिप ने UPS बोइंग 767 के अगले हिस्से नोज को टक्कर मार दी. एयरपोर्ट के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर ग्रेग चिन ने CNN को बताया कि रात करीब 9:15 बजे हुई इस टक्कर में दो लोग घायल हो गए. कोपा एयरलाइंस के यात्री सीजर फरेरा ने CNN को बताया, "हम लैंडिंग के बाद सामान्य गति से टैक्सी कर रहे थे, तभी अचानक मुझे अपने आस-पास लोगों की आवाज़ें तेज़ होती सुनाई दीं.

## कांग्रेस का 26 नवंबर को 'चलो दिल्ली' कार्यक्रम टला

**नई दिल्ली।** कांग्रेस ने 26 नवंबर के दिन को प्रस्तावित 'चलो दिल्ली' कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया है। संचार एजेंसी ANI के अनुसार पार्टी 26 नवंबर को सभी राज्यों की राजधानियों में 'संविधान रक्षा मार्च' आयोजित करेगी। यह कदम तब उठाया गया है, जब INDIA गठबंधन ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की थी। इस रैली का मकसद मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया का विरोध करना था। यह मार्च मिंटो रोड-कनॉट प्लेस जंक्शन से शुरू होकर रामलीला मैदान की ओर बढ़ा था। यह SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विपक्ष के देशव्यापी अभियान का हिस्सा था। इससे पहले, 31 अक्टूबर को राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक सार्वजनिक 'महाभियोग' कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इस रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष

# देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी

## राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना



**हैदराबाद।** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में आयोजित हुई कांग्रेस की भारत समिट को लेकर राहुल गांधी को जवाब दिया है। पुणे के एक कार्यक्रम में शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है। अगर राहुल जीतना चाहते हैं तो विदेश जाना छोड़े और गांवों में जाना शुरू करें। अमित शाह ने आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलग-अलग प्रकार से लगातार 3 बार हारने का फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। अभी कांग्रेस पार्टी ने भारत समिट 2026 हैदराबाद में आयोजित की। देश भर में वामपंथी विचारधारा के प्रचारकों को भारत में बुलाया। कांग्रेस के राजकुमार भी वहां गए। इस समिट का नाम भी भारत समिट रखा गया था, लेकिन राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत विरोधी विचार बोलकर पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का काम किया है।

### 12 साल में नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का 1 भी आरोप नहीं लगा

अमित शाह ने कहा, 'मैं आज इस मंच से महाराष्ट्र की जनता को कहने आया हूं और देश भर के लोगों को भी कहना चाहता हूं, जहां पर भी कांग्रेसी मिलें, आप उनको पूछें कि चुनाव लड़ना, हारना, जीतना, ये पार्टी के नेताओं के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। 10 साल का आपको मौका दिया था, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। देश की जनता ने आपका हाथ पकड़कर दिल्ली की सरकार के बाहर निकाल दिया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। 12 साल में नरेंद्र मोदी पर चार आने के भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है।'

### PM मोदी के कार्यकाल में भारत ने हर क्षेत्र में की ग्रोथ

उन्होंने आगे कहा कि चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचना हो, चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम बनानी हो, चाहे रेलवे उसका पुनरुद्धार करना हो, 76 एयरपोर्ट से 150 एयरपोर्ट बनाने हों, सबसे ज्यादा बड़ा मेट्रो का नेटवर्क लगाना हो, नई शिक्षा नीति लानी हो या सहकारिता मंत्रालय बनाना हो, ये सभी ये 12 साल के कार्यकाल में हुआ है।

### सत्ता चाहिए तो विदेश की यात्राएं बंद करें राहुल गांधी

अमित शाह ने कहा कि मैं राहुल गांधी को सलाह देना चाहता हूं कि इस तरह से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करके आपको सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता चाहिए तो विदेश की यात्राएं बंद करके भारत के गांव में जाना शुरू करिए तो शायद आपका नंबर कभी लग जाए। पूरी दुनिया जिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा कर रही है, आप उन नरेंद्र मोदी और भारत की विकास यात्रा को दुनिया में बदनाम करने का काम कर रहे हो। खैर, आप तो नहीं सुनेंगे लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि इसी दिशा में इनके पीछे चले तो अगले 30 साल तक आपका नंबर नहीं लगना है।

## राहुल के समर्थन में खुलकर बोले यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव

भारत समिट 2026 का आयोजन 13 और 14 नवंबर को तेलंगाना के हैदराबाद में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। इस समिट को लेकर शुरू से ही विवाद देखने को मिला। इसी बीच समिट में पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक का कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर किया गया समर्थन नए विवाद को जन्म दे दिया है। इसको लेकर केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आयोजन को लेकर सवाल खड़ा किए हैं। असल में महासचिव जियाकोमो फिलिबेक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकतंत्र और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर चलाए जा रहे अभियान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उस बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा की है, जिस पर हर लोकतंत्र की नींव टिकी होती है। यह सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट। जियाकोमो फिलिबेक ने अपने संबोधन में कहा कि मतदाता सूची को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए राहुल गांधी का अभियान लोकतंत्र की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने दो सप्ताह पहले रामलीला मैदान तक राहुल गांधी के साथ मार्च करने वाले हजारों लोगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र हमें अपने आप नहीं मिल जाता। इसकी रक्षा वे लोग करते हैं, जो इसके लिए खड़े होने का साहस रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए वे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं।

# अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे नहीं उड़े विमान



**वाशिंगटन।** अमेरिका में शुक्रवार 13 नवंबर को अचानक देशभर की उड़ानों पर रोक लगा दी गई. 9/11 हमले के बाद यह दूसरा मौका है जब पूरे अमेरिका में एक साथ विमानों को उड़ान भरने से रोकना पड़ा. हालांकि इस बार इसकी वजह कोई आतंकी हमला या सुरक्षा खतरा नहीं बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम में आई तकनीकी खराबी थी. अमेरिका का हवाई ट्रैफिक संभालने वाला सिस्टम अचानक ठीक से काम करना बंद कर गया. इसके बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने पूरे देश में ग्राउंड स्टॉप लगा दिया. यह रोक चार घंटे से ज्यादा समय तक रही. इस दौरान करीब 5 हजार उड़ानें रद्द होने की खबर है. अब उड़ानें दोबारा शुरू हो गई हैं लेकिन विमानों की आवाजाही सामान्य होने में अभी समय लग सकता है.

अमेरिकी परिवहन मंत्री शॉन डफी के मुताबिक शुक्रवार को अमेरिकी समय के अनुसार दोपहर 3:36 बजे रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हुई. इसके कुछ ही मिनट बाद करीब 3:54 बजे FAA ने पूरे अमेरिका में ग्राउंड स्टॉप लगाने का फैसला किया. रात करीब 8:15 बजे यह रोक हटा दी गई. भारतीय समय के मुताबिक शनिवार रात करीब 2:24 बजे उड़ानों पर रोक लगी और सुबह करीब 6:45 बजे इसे हटा लिया गया. यानी चार घंटे से ज्यादा समय तक नई उड़ानों को उड़ान भरने की इजाजत नहीं थी.

### ग्राउंड स्टॉप क्या होता है?

ग्राउंड स्टॉप का मतलब है कि एयरपोर्ट पर खड़े विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया जाता है. इस दौरान जो विमान पहले से आसमान में उड़ रहे होते हैं उन्हें अपनी मंजिल तक जाने और सुरक्षित उतरने की इजाजत रहती है लेकिन नए विमान उड़ान नहीं भर सकते. आमतौर पर खराब मौसम या किसी तकनीकी समस्या के चलते किसी एक एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टॉप लगाया जाता है लेकिन इस बार पूरे अमेरिका में एक साथ यह फैसला लिया गया. जिस तरह सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही को ट्रैफिक पुलिस संभालती है उसी तरह आसमान में विमानों की आवाजाही को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) संभालता है. अमेरिका के हवाई क्षेत्र को कई बड़े हिस्सों में बांटा गया है. हर हिस्से की जिम्मेदारी एक एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के पास होती है।

## अल्बानिया में फिर भड़की प्रदर्शन की आग, सड़कों पर झड़प

**नई दिल्ली।** अल्बानिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की एक बड़ी लहर चल रही है, जिसमें छात्र, विपक्ष के समर्थक और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री एडी रामा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. ये प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र हो गया है. अल्बानिया की राजधानी तिराना में छात्रों ने सड़कों के बीच कूड़े के डिब्बे को जलाकर सड़कों को जाम कर दिया. इस दौरान उन्होंने बस के शीशों को भी तोड़ दिया. तिराना में छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय तक विरोध प्रदर्शन किया. ये विरोध प्रदर्शन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, जेरेड कुशनर से जुड़े एक विवादित लग्जरी पर्यटन प्रोजेक्ट को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन अब ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार के आरोपों, खराब सार्वजनिक सेवाओं, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और विश्वविद्यालयों की बदहाल स्थिति के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुके हैं. पर्यावरण से जुड़े एक विरोध के रूप में मई 2026 में शुरू हुआ यह मामला अब छात्रों के नेतृत्व वाले एक बड़े सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है. प्रदर्शनकारी राजनीतिक जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, और कुछ लोग प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं. इस आंदोलन की मुख्य वजह साज़ान द्वीप और वजोसा-नार्टा के संरक्षित तटीय इलाके में प्रस्तावित एक लग्जरी पर्यटन प्रोजेक्ट है।

# BLA की कमान अब PAK सेना के पूर्व अधिकारी के हाथों में



**नई दिल्ली।** पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई लड़ने वाले संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) की कमान अब पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रहमान गुल उर्फ उस्ताद मुरीद को दी गई है. 42 वर्षीय कैप्टन रहमान गुल BLA का कमांडर इन चीफ बनने से पहले BLA के आत्मघाती दस्ते "मजीद ब्रिगेड" का डिप्टी कमांडर था. वो पिछले साल हुए जफर एक्सप्रेस हमले का मुख्य सूत्रधार भी था जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी FIA ने कैप्टन रहमान गुल पर 10 लाख का इनाम भी रखा था. बलूचिस्तान के नुस्की जिले के रहने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी के नए प्रमुख और पाकिस्तान की सेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रहमान गुल ने 18 साल की उमर में साल 2002 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का एग्जाम पास करके 109 वें PMA लांग कोर्स में काकुल स्थित पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया.

### कौन हैं रहमान गुल

वो बाद में पहले लेफ्टिनेंट और 2007 में कैप्टन के पद पर प्रमोट हुए. पाकिस्तानी सेना में अपनी तैनाती के दौरान कैप्टन रहमान गुल पाकिस्तानी सेना की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट (Frontier Force Regiment) का हिस्सा था, जो पाकिस्तान के वर्तमान में तीनो सेनाओं के प्रमुख आसिम मुनीर की भी रेजिमेंट है. हालांकि कैप्टन रहमान गुल फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 19 वीं बटालियन का अधिकारी था और आसिम मुनीर फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23 वीं बटालियन से ताल्लुक रखने वाला अधिकारी था. कैप्टन रहमान गुल ने पाकिस्तानी सेना में तैनाती के दौरान भारत-पाकिस्तान LoC पर कोटली सेक्टर में तैनाती के अलावा, खैबर पख्तूनख्वाह के दक्षिणी और उत्तरी वजीरिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियानों में भी हिस्सा लिया. हालांकि साल 2010 में कैप्टन रहमान गुल ने पाकिस्तानी सेना छोड़कर बलूच लिबरेशन आर्मी जॉइन कर ली >

### जेलेंस्की के सामने अमेरिकी ने रखी शर्तें

# यूक्रेन को NATO की मिलेगी सदस्यता लेकिन...



**वाशिंगटन।** यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार (13 नवंबर 2026) को रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दावा किया है. उन्होंने कहा कि हाल ही में अबू धाबी में हुई शांति वार्ता के दौरान, अमेरिका ने यह संभावना जताई थी कि यूक्रेन नाटो (NATO) की सदस्यता के बदले अपने पूर्वी डोनबास क्षेत्र से पीछे हट सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार पश्चिमी देशों से खास सुरक्षा गारंटी को लेकर बातचीत कर रही है.

ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा, "अमेरिकियों ने एक सवाल उठाया है कि क्या होगा अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए? क्या यूक्रेन डोनबास से पीछे हट जाएगा?' यह पहली बार था जब ऐसा कोई सवाल उठाया गया." ज़ेलेंस्की ने बताया कि सरकार नाटो और यूरोपीय संघ (EU) के साथ बातचीत कर रही है. जब पश्चिमी देश इन शर्तों की पुष्टि कर देंगे, तब वह इस प्रस्ताव के बारे में यूक्रेनी जनता से राय लेंगे. उन्होंने कहा, "इसके बाद मैं अपने यूक्रेनियों से पूछूंगा कि वे क्या सोचते हैं. क्या हमें इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं? मुझे अकेले यह फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है."

### नाटो का मुद्दा फिर से चर्चा में- ज़ेलेंस्की

ज़ेलेंस्की ने आगे कहा, "यही वजह है कि मुझे लगता है कि नाटो का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संकेत भी सुने होंगे. यह एक बेहद मुश्किल बातचीत है." ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय संघ और नाटो ही यूरोप की एकमात्र वास्तविक सुरक्षा हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि क्रेमलिन की तरफ से महाद्वीप की सुरक्षा व्यवस्था को बदलने की कोशिश से और अधिक युद्ध छिड़ सकते हैं. ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा, "यह खतरनाक है, क्योंकि मेरी नजर में ठीक ऐसी ही चीजें युद्ध या तनाव बढ़ने का कारण बनती हैं." उन्होंने कहा, "यूरोप में वास्तविक सुरक्षा का मतलब यूरोपीय संघ और नाटो है.

### अमेरिका की मध्यस्थता से बातचीत

रूस और यूक्रेन ने मंगलवार को साढ़े 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए 9 महीनों में पहली बार अमेरिका की मध्यस्थता से बातचीत की. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस बैठक को सही करार दिया है , जबकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह बातचीत रचनात्मक और काफी ठोस रही.

## मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने दी चेतावनी

**नई दिल्ली।** कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक सरकार का बयान आया है. राज्य सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने रविवार को कहा कि कानून हमारे पक्ष में है. खरगे ने आगे कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का भी बयान आया है. मेकेदातु बांध विवाद को लेकर प्रियांक खरगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमिलनाडु PCC अध्यक्ष तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए बयान देंगे और अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करेंगे.

इसी तरह कर्नाटक PCC अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने राज्य के हितों की रक्षा करें. उन्होंने आगे कहा कि हमारे व्यक्तिगत विचार चाहे जो भी हों, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और कानून हमारे पक्ष में है. जो भी होगा उससे दोनों राज्यों को फायदा ही होगा. असल में डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने कहा था कि देश के कानून का पालन तो सभी को करना ही पड़ता है।



## चावल-दाल और धान के स्टॉक पर लगी लिमिट

**नई दिल्ली।** रसोई का बजट बिगाड़ने वाली चावल और दाल की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है. बाजार में जमाखोरी रोकने और जरूरी खाद्य सामान की सप्लाई बनाए रखने के लिए स्टॉक पर नजर रखी जा रही है. तमिलनाडु सरकार ने धान, चावल और अरहर-उड़द दाल के भंडारण की सीमा तय कर दी है. वहीं, केंद्र सरकार ने देशभर में चावल और धान का स्टॉक रखने वाले कारोबारियों के लिए स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. यानी अब थोक कारोबारी, खुदरा दुकानदार, मिलर्स और प्रोसेसर्स अपनी मर्जी से तय सीमा से ज्यादा अनाज जमा नहीं रख सकेंगे. सरकार का मकसद है कि बाजार में सामान की कमी पैदा करके कोई कारोबारी कीमतें न बढ़ा सके. तमिलनाडु सरकार ने धान और चावल के लिए अलग-अलग कारोबारियों की भंडारण सीमा तय की है. नए आदेश के मुताबिक, थोक कारोबारी अधिकतम 2,000 मीट्रिक टन धान या चावल का स्टॉक रख सकेंगे. वहीं, खुदरा दुकानदार एक दुकान पर अधिकतम 8 टन सामान रख पाएंगे. चावल मिलों के लिए सीमा उनकी एक महीने की उत्पादन क्षमता के बराबर तय की गई है. प्रोसेसर्स के लिए भी उनकी मंथली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के आधार पर स्टॉक की सीमा तय की गई है. दालों के मामले में भी नियम बनाए गए हैं. थोक कारोबारी अरहर और उड़द दाल की हर किस्म का अधिकतम 200 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगे. खुदरा दुकानदारों के लिए यह सीमा प्रत्येक दाल की 5 टन तय की गई है.

## भारत में पेट्रोल डीजल की मांग 2034 तक बढ़ेगी

**नई दिल्ली।** भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का इस्तेमाल धीरे-धीरे बढ़ रहा है. सरकार भी पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. आने वाले सालों में देश की सड़कों पर पेट्रोल और डीजल की खपत कम होने के बजाय बढ़ती रह सकती है. इसकी बड़ी वजह वाहनों की बढ़ती संख्या और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट की जरूरतें हैं. एक नई रिपोर्ट में भारत के ईंधन बाजार को लेकर ऐसा ही अनुमान जताया गया है. भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखने को मिल रही है. पिछले साल देश में 24 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे. हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की यह बढ़ती लोकप्रियता फिलहाल कुल ईंधन की मांग में कमी लाने के लिए पर्याप्त नहीं है. आने वाले समय में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और पैसेंजर कारों का इस्तेमाल बढ़ने से पेट्रोल-डीजल की खपत पर असर पड़ सकता है. लंबे समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या कमर्शियल वाहनों से होने वाली ईंधन खपत की बढ़ोतरी पर भारी पड़ सकती है.

## छठ के दूसरे दिन महंगा हुआ सोना

**नई दिल्ली।** अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने वाले हैं तो बाजार के ताजा भाव जानना आपके लिए जरूरी है. पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी. हालांकि, 14 नवंबर के रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने में पिछले भाव के मुकाबले करीब 418 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है. दूसरी तरफ चांदी की कीमत में गिरावट आई है. चांदी करीब 2,666 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है. दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,40,664 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव करीब 1,28,848 रुपये प्रति 10 ग्राम है.।

# सात साल बाद भारत ने न्यूजीलैंड में जीती सीरीज

## पांचवें वनडे में गेंदबाजों ने दिलाई करिश्माई जीत



**नई दिल्ली।** न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे में भारत ने हारी हुई बाजी जीत ली है. माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले खेलने उतरी टीम इंडिया महज 209 रन ही बना सकी थी. जवाब में एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर दो विकेट पर 82 रन था. ऐसा लग रहा था कि कीवी टीम आसानी से यह मैच जीत लेगी और सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बाजी पलट दी. कीवी टीम 187 रनों पर ढेर हो गई. भारत ने 22 रनों से पांचवां वनडे जीता. इसके साथ ही पांच मैचों की सीरीज 3-1 से टीम इंडिया के नाम हुई.

न्यूजीलैंड में भारत ने सात साल बाद वनडे सीरीज जीती है. इससे पहले आखिरी बार टीम इंडिया ने 2018-19 में न्यूजीलैंड में पांच मैचों की वनडे सीरीज 4-1 से जीती थी. कीवी टीम भी अपने घर पर सात साल बाद वनडे सीरीज हारी है. भारत की इस जीत के हीरो रहे अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज. अर्शदीप ने 3 और सिराज ने 2 विकेट चटकाए. अर्शदीप ने अकेले ही न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर ध्वस्त किया. उन्होंने विल यंग (22 रन), क्रिस्टियन (16 रन) और निक केली (24 रन) को आउट किया. वहीं सिराज ने फिन एलन (01) और टिम सीफर्ट (14 रन) को पवेलियन भेजा. 210 रनों के मामूली से लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. 26 के कुल स्कोर पर उसका पहला विकेट गिरा. टिम सीफर्ट 21 गेंद में दो चौकों की मदद से 14 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद विल यंग और निक केली ने 38 रनों की साझेदारी की. यंग 42 गेंद में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे. उन्होंने तीन चौके लगाए. वहीं केली 45 गेंद में दो चौकों की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए. एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर दो विकेट पर 82 रन था, लेकिन फिर 83 रनों पर उन्होंने 4 विकेट गंवा दिए. इसके बाद डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और माइकल ब्रेसवेल ने मोर्चा संभाला. दोनों ने 36 रनों की साझेदारी की. हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने दोनों को सेट होने के बावजूद आउट कर दिया. फॉक्सक्रॉफ्ट 42 गेंद में 31 और ब्रेसवेल 33 गेंद में 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे. 119 पर न्यूजीलैंड का पांचवां विकेट गिरा और 119 पर ही छठा विकेट भी गिरा. इसके बाद मिचेल सैंटनर और क्रिस्टियन क्लार्क ने 39 रनों की साझेदारी कर दी. सैंटनर ने 31 गेंद में एक चौके और दो छक्के की मदद से 24 रन बनाए. वहीं क्लार्क 35 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए. अब न्यूजीलैंड का स्कोर 158-6 से 161-8 हो गया था. इसके बाद ब्लेयर टिक्नर और और डैकब डफी ने 20 रनों की साझेदारी की, और न्यूजीलैंड की उम्मीद फिर से जगा दी. लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मैच पलटने नहीं दिया।



## गेंदबाज आपको सीरीज जिताते हैं: गौतम गंभीर

**नई दिल्ली।** न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने में भारतीय गेंदबाजों का बल्लेबाजों के मुकाबले ज्यादा योगदान रहा. बे ओवल में आज खेले गए आखिरी वनडे में भी ऐसा ही नजर आया. विराट कोहली (5), रोहित शर्मा (7), ऋतुराज गायकवाड़ (18), श्रेयस अय्यर (22) के रूप में टॉप-4 बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए. भारत की पूरी टीम 209 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. इस छोटे टोटल को डिफेंड करना मुश्किल था, लेकिन गेंदबाजों ने कर दिखाया. गौतम गंभीर ने मैच और सीरीज जीतने के बाद गेंदबाजों की तारीफ में एक पोस्ट किया. पांचवें वनडे के प्लेयर ऑफ द मैच अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, और 10 ओवर में सिर्फ 3 की इकॉनमी से 30 रन दिए. मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए. अक्षर पटेल ने भी 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, उन्होंने बल्ले से भी 46 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारत ने न्यूजीलैंड को 187 रनों पर समेट दिया, जिससे भारत ने 22 रनों से मैच जीत लिया और सीरीज 3-1 से अपने नाम की. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ ली गई फोटो शेयर करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "गेंदबाज आपको सीरीज जिताते हैं!

# मोहम्मद सिराज का कोच गंभीर और BCCI को क्लियर मैसेज



**नई दिल्ली।** मोहम्मद सिराज पूरे साल 2026 में कुल मिलाकर सिर्फ पांच ODI मैच खेल पाए हैं. कभी टीम इंडिया के मुख्य गेंदबाजों में से एक रहने वाले सिराज को अब लगभग पूरी सीरीज में बाहर बैठना पड़ रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी वनडे में सिराज को आखिरकार मौका मिला. इस एक मौके के बलबूते उन्होंने बीसीसीआई की चयन समिति और कोच गौतम गंभीर को भी क्लियर मैसेज दे दिया है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मैनेजमेंट ने लगातार युवा गेंदबाजों पर भरोसा दिखाया था. पांचवें मैच में सिराज ने अपने पहले 8 ओवरों में सिर्फ 30 रन देकर 2 विकेट चटकाए. सिराज ने पहले टीम सीफर्ट और फिर फिन एलन का विकेट चटकाया. उन्होंने सिर्फ विकेट ही नहीं चटकाए बल्कि रन गति पर भी लगाम कसी. सिराज नियमित रूप से वनडे स्क्वाड का हिस्सा बने रहे हैं, लेकिन प्लेइंग इलेवन में उनकी मौजूदगी सवालों के घेरे में रही है. इस साल सिर्फ पांच वनडे मैच खेलना बड़े सवाल खड़े करता है कि सिराज एक सीनियर गेंदबाज होते हुए भी अगले साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे भी या नहीं. 2023 ODI वर्ल्ड कप में सिराज भारत के लिए प्रभावी गेंदबाज साबित हुए थे. उन्होंने मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का बखूबी साथ निभाते हुए 11 मैचों में कुल 14 विकेट चटकाए थे।

# पाकिस्तान को धोने का मिला इनाम मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री!



**नई दिल्ली।** मोहित उल्वा ने ओमान में बीते शनिवार (14 नवंबर) 2026 अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए शानदार पारी खेली. उन्होंने नंबर-10 पर बैटिंग करते हुए 26 गेंद में 5 चौके और 3 छक्के लगाकर 49* रन बनाए. मोहित ने भारत के लिए विनिंग शॉट खेला, जब टीम को आखिरी गेंद में 3 रन चाहिए थे. उन्होंने चौका लगाकर टीम इंडिया को खिताब जितवाया. अब मोहित को इस शानदार पारी का इनाम मिला है. गुजरात के सुरेंद्रनगर से आने वाले 18 वर्षी मोहित को 2026 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए सौराष्ट्र टीम से जोड़ लिया गया है. मोहित तेज गेंदबाज के रूप में अपना क्रिकेट खेलते हैं. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बल्ले से कमाल करके सबका ध्यान खींचा.

टी20 फॉर्मेट में खेली जाने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सौराष्ट्र ने बीते शनिवार को पहला मुकाबला बिहार के खिलाफ खेल लिया. मैच में सौराष्ट्र ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी. क्रिकबज के मुताबिक, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जयदेव शाह ने मोहित के टीम से जुड़ने की पुष्टि की है।

## e-Challan भेजकर 6 लाख ठग उसी से बैंकर ने भरे अपने क्रेडिट कार्ड बिल

**नई दिल्ली।** मोबाइल पर आने वाला एक छोटा-सा ट्रैफिक चालान का मैसेज आपकी जिंदगी भर की कमाई पर भारी पड़ सकता है. साइबर अपराधी अब सरकारी विभागों के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं.ऐसा ही एक मामला ओडिशा के राउरकेला से सामने आया है, जहां फर्जी ई-चालान के जरिए एक व्यक्ति के बैंक खाते से करीब 6 लाख रुपये निकाल लिए गए. पुलिस ने इस मामले में मुंबई से एक बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है.लिंक खोलने के कुछ ही समय बाद पीड़ित के मोबाइल पर लगातार OTP आने लगे. जब उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो पता चला कि बिना अनुमति के छह UPI ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं. इन लेनदेन के जरिए खाते से करीब 5.99 लाख रुपये निकाल लिए गए. घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद राउरकेला पुलिस ने बैंक खातों और पैसों के लेनदेन से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड की जांच शुरू की.राउरकेला के एक निवासी को 30 मई की रात करीब 10:30 बजे WhatsApp पर ट्रैफिक ई-चालान से जुड़ा मैसेज मिला था. इसमें दावा किया गया कि वाहन पर जुर्माना लगा है और इसे जमा करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में 500 रुपये का भुगतान करना होगा।

# 22660 करोड़ के पार पहुंचा पतंजलि फूड्स का कारोबार



**नई दिल्ली।** पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने 30 सितंबर 2026 को खत्म हुई दूसरी तिमाही और पहली छमाही के अपने अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा कर दी है. कंपनी ने इस अवधि में मजबूत प्रदर्शन करते हुए अब तक का सबसे अधिक राजस्व दर्ज किया है, जिसमें खाद्य तेल, पाम ऑयल प्लांटेशन और एफएमसीजी कारोबार की अहम भूमिका रही है. इस तिमाही के दौरान देश में महंगाई का दबाव बढ़ता हुआ नजर आया. जुलाई 2026 में खुदरा महंगाई लगभग 4.45% थी, जो अगस्त में बढ़कर 4.82% और सितंबर में 5.54% हो गई. जनवरी 2026 में नए सीपीआई आंकड़े आने के बाद यह महंगाई का सबसे ऊंचा स्तर रहा. खाद्य महंगाई बढ़कर 7.7% हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आना था. कम बारिश और एल नीनो के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर अधिक दिखा, हालांकि खेती के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य कामों से हुई आमदनी ने लोगों को सहारा दिया.

### Q2 FY27 के मुख्य वित्तीय आंकड़े

कंपनी का दूसरी तिमाही में परिचालन से राजस्व 11,322.58 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के 9,798.84 करोड़ की तुलना में 15.55% की सालाना वृद्धि दर्शाता है. तिमाही के दौरान प्रमुख आंकड़े इस प्रकार रहे...

एफएमसीजी कारोबार राजस्व: 2,923.48 करोड़

एबिटडा (कुल आय आधार पर): 509.55 करोड़

एफएमसीजी एबिटडा: 221.33 करोड़

सकल लाभ:1,439.14 करोड़ (सकल लाभ मार्जिन 12.62%)

परिचालन एबिटडा (असाधारण मदों को छोड़कर):425.63 करोड़ (मार्जिन 3.76%)

कर पूर्व लाभ (PBT): 409.02 करोड़ (मार्जिन 3.59%)

अन्य आय स्रोत:निर्यात से 29.09 करोड़ और विंड टर्बाइन पावर जनरेशन से 10.63 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ.

### फेसबुक ने गैलरी से चुराए फोटो

# इटली ने Meta पर लगाया 8000 करोड़ का जुर्माना




**नई दिल्ली।** सोशल मीडिया कंपनी Meta को इटली में बड़ा झटका लगा है. इटली की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी पर 805 मिलियन यूरो (करीब 8000 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है. Meta पर आरोप है कि उसने एड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाले फेसबुक यूजर्स की निजी फोटो और वीडियो उनकी परमिशन के बिना एक्सेस किए.इस मामले में इटली के करीब 2 करोड़ यूजर्स जो एंड्रॉयड फोन या स्मार्टफोन चलाते हैं, वो प्रभावित हो हुए हैं. मामले शिकायत मिलने पर तुरंत इसकी जांच इटली की एजेंसी ने शुरू की और कार्रवाई भी की जा रही है.

### क्या है पूरा मामला?

दरअसल फेसबुक में एक ऐसा फीचर दिया गया है, जिसका नाम Get suggestions from gallery when browsing Facebook है. इस फीचर के जरिए यूजर्स को फेसबुक चलाते समय उनके मोबाइल की गैलरी के फोटोज और वीडियो पोस्ट करने के लिए सजेशन मिलता है. इटली की जांच एजेंसी के मुताबिक, इस फीचर के जरिए फेसबुक यूजर्स के फोन की गैलरी तक पहुंच रहा है. लेकिन यूजर्स को साफ तौर पर ये नहीं बताया गया कि एप उनकी निजी फोटो और वीडियो तक पहुंच सकता है.इस जांच में ये भी सामने आया कि फोटो गैलरी का एक्सेस लेने के लिए एक ही अनुमति मांगी जाती है, जो एप के कई फीचर्स के लिए इस्तेमाल होती है. ये फीचर डिफॉल्ट रूप से चालू भी था.

### Meta बदलेगा सिस्टम

इटली की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मेटा को 60 दिन का समय दिया है. कंपनी को अब इस फीचर के लिए यूजर्स से अलग और स्पष्ट अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा कंपनी को ये फीचर डिफॉल्ट के रूप से बंद रखना होगा. यूजर्स की सहमति मिलने के बाद ही इसे चालू किया जा सकेगा.

### AI ट्रेनिंग को लेकर नहीं हुई जांच

इस मामले में एक और जरूरी बात सामने आई है. इटली की जांच में ये पता लगाने की कोशिश नहीं की गई कि मेटा ने यूजर्स की फोटो और वीडियो का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को ट्रेनिंग देने के लिए किया या नहीं. मेटा ने AI ट्रेनिंग के लिए इन फोटोज का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है.हालांकि, इटली की अथॉरिटी ने कहा है कि वो साल 2026 में शुरू हुए एक नए फीचर की अलग से जांच कर सकती है. इस फीचर के जरिए फोन की गैलरी के कंटेंट को क्लाउड पर प्रोसेस किया जा सकता है. इटली की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस मामले में मेटा पर करीब 800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस पूरे वाक्ये में करीब 2 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं।

## PNB Scam: 6 अफसरों की ID चुराकर फ्रॉड, कुर्सी खाली देखते ही बैठ जाती थी

**नई दिल्ली।** उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की एक ब्रांच में करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. बैंक की सेक्टर पाई-1 ब्रांच में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी पर आरोप है कि उसने 6 बैंक अधिकारियों की लॉगिन ID का इस्तेमाल करके ग्राहकों के खातों से पैसे ट्रांसफर किए. इस मामले में हाल ही में CCTV फुटेज भी सामने आया है. इसमें महिला कर्मचारी दूसरे अधिकारियों की खाली कुर्सियों पर बैठकर उनके कंप्यूटर चलाती दिखाई दी. मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है.न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक बैंक की शुरुआती जांच में ग्राहकों के खातों से करीब 10.24 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन का पता चला है. हालांकि, कुछ ग्राहकों का दावा है कि उनके सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से करीब 35 करोड़ रुपये गायब हैं. बताया जा रहा है कि इनमें कई किसान भी शामिल हैं. इन किसानों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन के बदले मिले मुआवजे की रकम बैंक में जमा की थी. बैंक की शिकायत के मुताबिक, महिला कर्मचारी दीपांशी शर्मा ने 6 अधिकारियों की लॉगिन ID का गलत इस्तेमाल किया.।

# गन्ने के मंडप में पूजा, सूप में ठेकुआ फल सजाए डूबते सूर्य अर्घ्य

## आज छत्तीसगढ़ में उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी छठव्रती



**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ में लोक आस्था के महापर्व छठ पर रविवार शाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। व्रती महिलाएं सूप और दउरा में फल, ठेकुआ और प्रसाद सजाकर घाट पहुंची। ढोल-नगाड़ों के बीच डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बिलासपुर में अरपा नदी के तट पर 1 किलोमीटर लंबा घाट तैयार किया गया है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। यहां 5100 दीप जलाकर महाआरती की जाएगी। रायपुर में महादेव घाट जाने वाले रास्ते में 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था।





महादेव घाट पर रविवार को छठ महापर्व के अवसर पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। सूर्य उपासना के इस पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पर पहुंचे और विधि-विधान से छठी मैया तथा भगवान सूर्यदेव की पूजा-अर्चना की। व्रती महिलाओं और पुरुषों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और संतान की दीर्घायु की कामना की। महादेव घाट पर छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहा। पारंपरिक वेशभूषा में सजे व्रती हाथों में पूजा की टोकरी और सूप लेकर घाट पहुंचे। पूजन सामग्री में फल, ठेकुआ, नारियल, गन्ना और अन्य पारंपरिक प्रसाद शामिल रहे। सूर्यास्त के समय नदी के जल में खड़े होकर श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान छठी मैया के पारंपरिक गीतों और भक्ति भाव से पूरा घाट भक्तिमय नजर आया। छठ महापर्व के अवसर पर महादेव घाट का वातावरण धार्मिक उल्लास से सराबोर रहा। परिवारों के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान और परंपरा के साथ पूजा में हिस्सा लिया। छठ पूजा लोक आस्था, प्रकृति और सूर्य उपासना का महापर्व है, जिसमें कठिन व्रत, अनुशासन, पवित्रता और सामूहिक सहभागिता का विशेष महत्व है।

### घाट पर हुई महाआरती, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समां

महादेव घाट पर छठ महापर्व के अवसर पर विशेष महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन निर्धारित किया गया था। लोक गायिका गायत्री यादव, मुकुल सिंह और इशरत जहां केडिया की प्रस्तुतियों के साथ छठ गीतों की गूंज से वातावरण को भक्तिमय बनाने की तैयारी थी। छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां भी कार्यक्रम का आकर्षण रहीं। आयोजन समिति के अनुसार, रायपुर में महादेव घाट सहित 50 से अधिक स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। चार दिवसीय इस महापर्व का समापन सोमवार, 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। इसके बाद व्रती अपना निर्जला व्रत पूरा कर पारण करेंगे। छठ पूजा ने एक बार फिर सामाजिक समरसता, लोक संस्कृति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संदेश दिया। महादेव घाट पर उमड़ी श्रद्धा ने राजधानी में छठ महापर्व की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को रेखांकित किया।



## मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तपकरा में छठ महापर्व पर दिया संध्या अर्घ्य




**रायपुर।** मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जशपुर जिले के तपकरा में छठ महापर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अस्ताचलगामी भगवान सूर्यदेव को संध्या अर्घ्य अर्पित कर छठी मैया से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और कल्याण की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने सभी को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने तपकरा में छठ घाट निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में छठ महापर्व के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुनकुरी में 5 करोड़ रुपए की लागत से छठ घाट का सौंदर्यीकरण किया गया है, वहीं दराखारिका में 4 करोड़ रुपए की लागत से नए छठ घाट का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व लोक आस्था, तपस्या और समर्पण का अनुपम प्रतीक है, जो हमें प्रकृति, जल और सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर श्रीमती कौशल्या साय, जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमन्ती साय, भरत साय सहित जनप्रतिनिधि, छठ व्रती महिलाएं एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

## वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायगढ़ के कयाघाट में छठ महापर्व के संध्या अर्घ्य में हुए शामिल



**रायपुर।** वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी लोक आस्था, श्रद्धा और पवित्रता के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर रायगढ़ के जूटमिल स्थित कयाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने छठ महापर्व के तीसरे दिन आयोजित संध्या अर्घ्य में सम्मिलित होकर व्रती माताओं-बहनों एवं क्षेत्रवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छठी मइया एवं भगवान सूर्यदेव से सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना की। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छठ महापर्व हमारी समृद्ध लोक परंपरा, अटूट आस्था और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। सूर्य उपासना का यह पावन पर्व हमें संयम, अनुशासन, पवित्रता और समर्पण की प्रेरणा देता है। अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने की यह अनूठी परंपरा प्रकृति और मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि छठ महापर्व में व्रती माताएं एवं बहनें अपने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान के कल्याण और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ श्रद्धापूर्वक व्रत रखती हैं। यह पर्व पारिवारिक स्नेह, सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे की भावना को और मजबूत करता है। छठ पूजा हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने के साथ ही प्रकृति के संरक्षण और स्वच्छता का संदेश भी देती है।

# साय के सुशासन में कम पैदावार में भी अन्नदाताओं को पूरा लाभ



मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

आज से धान उपार्जन केंद्र में पूजा-अर्चना के साथ धान खरीदी का शुभारंभ होते ही किसानों में उत्साह दिखा। साय के सुशासन में कम पैदावार में भी अन्नदाताओं को पूरा लाभ दिए जाने की घोषणा के बाद किसानों में उत्साह की लहार है। हालांकि कुछ जगहों में व्यवहारिक और तकनीकि दिक्कतों की वजह से किसानों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप आज 15 नवंबर से रायपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह, उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है।

## रायपुर में कलेक्टर ने खुद जांची नमी, कराया तौल

रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जोरा, आरंग के मुरेठी और नगपुरा केंद्र पहुंचकर खरीदी शुरू कराई। इस दौरान पूजा-अर्चना भी की गई। नगपुरा केंद्र में कलेक्टर ने नमी मापक यंत्र से धान की जांच की और खुद तौल भी कराया। उन्होंने खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्रों में किसानों के लिए पेयजल, छांव और बैठने की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के उपाध्यक्ष श्री अभिनेष कश्यप एवं नगर पंचायत चंदखुरी के अध्यक्ष श्री प्रतीक बैस ने विधिवत पूजा-अर्चना कर धान खरीदी की शुरुआत की। कलेक्टर ने नमी मापक यंत्र से धान की नमी जांची तथा धान का तौल भी किया। धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह देखा गया। उपार्जन केंद्र में किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, छाया, बैठने सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, एसडीएम रवि सिंह, डीसीसीबी भूपेश चंद्रवंशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे।

### सारंगढ़-बिलाईगढ़ के 95 केंद्रों में धान खरीदी

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के 95 खरीदी केंद्रों में किसान अपनी फसल बेच सकेंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों को सही तरीके से धान खरीदी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खरीदी में गड़बड़ी और लापरवाही नहीं करने को कहा है। साथ ही पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी रखने के निर्देश दिए हैं।



### कोरबा में किसान ने बेचा 12.80 क्विंटल धान

कोरबा जिले के सभी 68 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी शुरू हो गई है। हरदीबाजार केंद्र में पूजा-अर्चना कर खरीदी का शुभारंभ किया गया। पहली किसान गीतांजलि डहरिया का माला पहनाकर सम्मान किया गया। उन्होंने 12 क्विंटल 80 किलो धान बेचा। विधायक प्रतिनिधि नरेश टंडन ने कहा कि किसानों को धान बेचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। केंद्रों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं रखी जाएं और किसानों का सम्मान किया जाए।

### निगरानी के लिए कमांड सेंटर बनाया

धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने और व्यवस्था पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है। 4 नवंबर को जिला और तहसील स्तर पर जांच समितियों और उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है।

### शिकायत के लिए हेल्पलाइन जारी

कमांड सेंटर के नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर ओंकार यादव बनाए गए हैं। खरीदी की निगरानी रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 9691901259 जारी किया गया है।

### 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक बेच सकेंगे धान

इस खरीफ सीजन में किसान 1 एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान बेच सकेंगे। सरकार ने धान का भाव 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इस हिसाब से एक एकड़ में पूरी 21 क्विंटल उपज बेचने पर किसान को 65,100 रुपए मिलेंगे। इसी तरह दो एकड़ में 42 क्विंटल धान बेचने पर 1 लाख 30 हजार 200 रुपए मिलेंगे। वहीं, पांच एकड़ में 105 क्विंटल धान बेचने पर किसान को 3 लाख 25 हजार 500 रुपए मिलेंगे। वास्तविक खरीदी किसान के पंजीकृत रकबे और उपलब्ध उपज के आधार पर होगी।

### 360 नए खरीदी केंद्रों से मिलेगी राहत

सरकार ने इस बार धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2740 से बढ़ाकर 3100 कर दी है। यानी पिछले साल के मुकाबले 360 नए केंद्र बनाए गए हैं। इससे दूरस्थ गांवों के किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। खरीदी केंद्रों पर बारदाने, तौल मशीन, नमी मापक यंत्र और धान के भंडारण की व्यवस्था भी जरूरी होगी।

### तुंहर टोकन ऐप से घर बैठे बुक कर सकेंगे टोकन

इस बार धान बेचने के लिए टोकन व्यवस्था को डिजिटल किया गया है। किसान तुंहर टोकन ऐप के जरिए घर बैठे धान बेचने का टोकन बुक कर सकेंगे। इसके अलावा समितियों से भी टोकन जारी किए जाएंगे। इससे किसानों को टोकन लेने के लिए बार-बार सोसायटी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

## दुर्ग- रकबा कटने से किसान ने दी आत्महत्या की चेतावनी

**शहर सत्ता/रायपुर/दुर्ग/सुकमा।** छत्तीसगढ़ में आज (15 नवंबर) से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। इस साल किसानों को धान के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। पहले दिन किसानों को अलग-अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुर्ग में डेढ़ एकड़ रकबा कटने से 33 क्विंटल धान बेचने में परेशान किसान ने आत्महत्या की बात कही। कांग्रेस ने इसे षडयंत्र बताया और किसानों का पूरा धान खरीदे जाने की मांग की है। किसी किसान को ऑनलाइन टोकन की तारीख जनवरी में मिल रही है, तो किसी का पंजीकृत रकबा कम होने से धान बेचने में दिक्कत हो रही है। किसानों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखीं। धमतरी में पहले दिन 550 से ज्यादा किसानों ने टोकन कटवाया। वहीं, सुकमा में किसी भी किसान का टोकन नहीं कटा। दोपहर 12 बजे तक जिला मुख्यालय के खरीदी केंद्र में न किसान पहुंचे और न ही धान से भरी गाड़ियां आईं। जबकि केंद्र में खरीदी की पूरी तैयारी थी। प्रदेश में 27.50 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। इस बार खरीदी केंद्रों की संख्या 2740 से बढ़ाकर 3100 कर दी गई है। टोकन काटने, किसान पंजीयन और खेत में बोई गई फसल की जांच की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जा रही है।

### ऑनलाइन टोकन की तारिश जनवरी में मिली

दुर्ग जिले के 123 केंद्रों में धान खरीदी शुरू हुई। अंडा खरीदी केंद्र में पहुंचे जंजगिरी के किसान तुलाराम देशमुख को ऑनलाइन टोकन की तारीख 21 जनवरी मिली। उन्होंने ऑफलाइन टोकन के लिए केंद्र में नाम दर्ज कराया है।

### डेढ़ एकड़ रकबा कटा, 33 क्विंटल धान नहीं बिकेगा

दुर्ग में किसान शिवप्रसाद निर्मलकर ने बताया कि रिकॉर्ड में 67 आर जमीन कम हो गई है। इससे करीब 33 क्विंटल धान नहीं बेच पाएंगे। उन्होंने कर्ज लेकर खेती की है। कलेक्टर से शिकायत के बाद रकबे से जुड़ी गलती सुधारकर दो-तीन दिन में मुख्य कार्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

### सुकमा में पहले दिन टोकन नहीं कटा

सुकमा जिले में धान खरीदी के पहले दिन किसी किसान का टोकन नहीं कटा। दोपहर 12 बजे तक जिला मुख्यालय के खरीदी केंद्र में न किसान पहुंचे और न ही धान से भरी गाड़ियां आईं। केंद्रों में कांटा पूजन के साथ तैयारियां पूरी थीं, लेकिन खरीदी शुरू नहीं हो सकी। कर्मचारी और अधिकारी किसानों का इंतजार करते रहे। जिले में धान खरीदी के लिए 27 समितियां बनाई गई हैं। इनमें 18,641 किसानों ने पंजीयन कराया है।

## 36000 करोड़ की बचत

बिना 21 क्विंटल धान के भी पूरे बोनस देने के फैसले का भले ही आदेश नहीं अभी नहीं निकला है मगर फूड सिकेट्री रीना कंगाले ने कलेक्टरों के वीसी में जो बताया, वह बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल, ये सिर्फ कलेक्टरों के उपर नहीं छोड़ना चाहिए। मंत्रियों और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को भी इस काम में लगना होगा। किसानों को बताना होगा कि आप एक एकड़ में भले ही पांच क्विंटल धान उपजाओ, बोनस 21 क्विंटल के हिसाब से मिलेगा। इस फैसले से सबसे अधिक नुकसान बिचौलिये और राईस मिलरों को होगा। हो सकता है, सरकार में बैठे लोगों के जरिये भी वो इसके खिलाफ नैरेटिव बनाने का प्रयास करें। मगर यह तय है कि यह फैसला अगर प्रभावशील हो गया तो 2028 के विधानसभा चुनाव तक सरकार के खजाने में कम-से-कम 36 हजार करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे, जो फर्जी धान खरीदी के चलते बिचौलियों और राईस मिलरों की जेब में जाते हैं। बता दें, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का रेट और उस पर 1300 रुपए प्रॉसेसिंग लागत। याने 4400 का एक क्विंटल धान पड़ता है। करीब 30 लाख मीट्रिक टन धान कागजों में खरीदा जाता है या फिर रिसाइकिलिंग होती है। बिना 21 क्विंटल धान के पूरा बोनस देने से हर साल मिनिमम 12 हजार करोड़ बचेगा। हो सकता है 15000 करोड़ भी हो जाए। इस 36 हजार करोड़ से सरकार राज्य के डेवलपमेंट के लिए बड़ा काम कर सकती है।

### कोआर्डिनेशन की कमी?

धान खरीदी सिर्फ फूड और मार्कफेड का काम नहीं। कायदे से इसमें फूड के साथ रेवेन्य और एग्रीकल्चर का कोआर्डिनेशन बहुत जरूरी है। किसानों को बोनस कृषि विभाग देता है। इसके लिए सरकार बजट में प्रावधान करती है। तीनों विभागों के सचिवों की एक कमेटी बनाकर महीने भर पहले इस पर काम शुरू कर देना चाहिए था। जैसे मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई जाती है, उस तरह किसी गंभीर और अनेक विभाग से जुड़े मसलों को लेकर एक हाई पावर कमेटी बनाई जानी चाहिए। फिर मंत्रियों और विधायकों को कंविस करना पड़ेगा कि राईस मिलरों और कोचियों की जेब में पैसा न जाने से आप चुनाव नहीं हारोगे। पिछले साल



ऐसा ही तो हुआ था। सरकार ने जब सिस्टम को टाईट किया तो मंत्रियों और नेताओं में त्राहि माम मच गया था। बात पते की यह है कि राजनीतिक दलों को राज्य की चिंता भी जरूरी है। आखिर, पंजाब में देख ही रहे, क्या हो रहा। जीडीपी में देश में तीसरे नंबर पर आने वाला राज्य 16 वें नंबर पर है। और कर्मचारियों का बकाया 17 हजार करोड़ डीए न देने पर कोर्ट ने वहां के मुख्य सचिव को जुर्माना किया है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27